मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com | ग्वालियर, मंगलवार 27 अक्टूबर 2026 | वर्ष-08, अंक-196, पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए | Website: www.eksatbulletin.in

मुख्यमंत्री ने मां बगलामुखी देवी लोक के पहले चरण में होने वाले 85.40 करोड़ रूपए लागत के कार्यों का किया भूमि-पूजन

आस्था, अध्यात्म, श्रद्धा और धार्मिक पर्यटन का बड़ा केन्द्र बनेगा मां बगलामुखी देवी लोक

एक सत बुलेटिन, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आने वाले समय में नलखेड़ा में बन रहा मां बगलामुखी देवी लोक आस्था, अध्यात्म, श्रद्धा, अनुभव और धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केन्द्र बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि देश-दुनिया से नलखेड़ा आने वाले श्रद्धालुओं को अब यहां विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को आगर-मालवा जिले की सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के नलखेड़ा में विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर परिसर में प्रस्तावित भव्य देवी लोक परियोजना का भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पहले मां बगलामुखी मंदिर पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए, विधि-विधान से पूजा-अर्चना की तथा प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने भव्य देवी लोक परियोजना के प्रथम चरण के कार्यों का भूमि-पूजन कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने



दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सिंगल क्लिक से निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन किया। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री तथा आगर-मालवा जिले के प्रभारी मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, विधायक श्री भैरव सिंह बापू एवं पूर्व विधायक श्री राणा विक्रम सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मां बगलामुखी देवी की तस्वीर एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज नलखेड़ा में 85.40 करोड़ रुपए लागत के मां बगलामुखी देवी लोक का भूमि-पूजन हुआ है। यहां की महिमा अद्भुत है। मां सभी की मनोकामनाएँ पूरी करती हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा हुए उज्जैन में श्रीमहाकाल लोक के लोकार्पण के बाद पूरा मालवांचल का वातावरण बदल गया है। अब मां बगलामुखी देवी लोक के विकास कार्यों को गति दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नलखेड़ा के मार्ग में आने वाली पुलिया और सड़क को आवश्यकतानुसार चौड़ा किया जाएगा, जिससे आवागमन में कोई परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि आमला से नलखेड़ा तक 55 करोड़ रूपए से अधिक की लागत से लगभग 14 किमी लंबा एक नया बायपास भी बनाया जा रहा है। इस नए फोरलेन के भूमि-पूजन के माध्यम से नागरिकों को बड़ी सौगात मिल रही है। उन्होंने बताया कि लखुंदर नदी पर श्रद्धालुओं के सुरक्षित और सुगम आवागमन के लिए 13.77 करोड़ की लागत से एक नया और विशाल उच्च स्तरीय पुल भी बनाया जा रहा है। साथ ही इस स्थान की सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी भी मजबूत की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा बैजनाथ का भी भव्य-दिव्य धाम बन रहा है। मां बगलामुखी का धाम भी ऐसा ही भव्य बनेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 14 से अधिक धार्मिक स्थलों को दिव्यलोक बनाने का संकल्प लिया है। इसमें श्रीराम की नगरी ओरछा, उज्जैन में महाकाल लोक, ओंकारेश्वर में एकात्म धाम, चित्रकूट धाम भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि नलखेड़ा में लखुंदर नदी के तटों पर सुंदर और भव्य घाट बनाए जाएंगे। यहां पूरे परिसर और पार्किंग क्षेत्र का विस्तार होगा। साफ-सुथरे शौचालय, पक्की सड़कें और अतिथियों के लिए भवन भी बनाया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए धर्मशालाओं में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां बगलामुखी के आशीर्वाद से इस वर्ष अलनीनो का प्रभाव कम रहा है और अच्छी बारिश के साथ सोयाबीन की फसल भरपूर हुई है।

बंगाल सीएम बोले- कॉकरोचों को पनपने न दें

एजेन्सी, कलकत्ता



पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि दिमागी नक्सल , टुकड़े-टुकड़े गैंग और कॉकरोचों को पनपने न दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हों। सुवेंदु ने यह बातें तमलुक में भाजपा के पार्टी कार्यालय के भूमि पूजन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही।

दो दिन में यह दूसरी बार है जब सुवेंदु ने कॉकरोच पार्टी पर निशाना साधा। रविवार को भी रामनगर में एक कार्यक्रम में सुवेंदु ने कहा था कॉकरोच, खटमल जैसी बुराइयां कोरोना वायरस की तरह फैलने की कोशिश कर रही हैं। इन्हें कीटनाशक स्प्रे हिट से ही खत्म किया जा सकता है।

ममता राज्य को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहती थीं: ममता सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति की। ममता को राष्ट्रवाद की कोई समझ नहीं थी और वह राज्य को ह्यग्रेटर बांग्लादेशह्ण में बदलने की योजना बना रही थी।

ममता ने विरासत और संस्कृति को मिटाने की कोशिश की: 34 साल तक शासन करने वाले वामपंथी और 15 साल तक सत्ता में रही TMC सरकार ने लोगों की विरासत और संस्कृति को मिटाने की कोशिश की।

NCC में छात्रों का नामांकन रोकने की कोशिश: TMC सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय कैडेट कोर में छात्रों के नामांकन को रोकने की कोशिश की और उसकी जगह जय हिंद वाहिनी शुरू की। उन्होंने कहा कि ठउउ में शामिल होने से छात्रों को सशस्त्र बलों में अग्निवीर के रूप में चयन में मदद मिल सकती थी।

ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर वायुसेना प्रमुख ने चेताया पाकिस्तान

कोई भी टारगेट इंडियन एयरफोर्स की पहुंच से दूर नहीं : एपी सिंह

एजेन्सी, नई दिल्ली

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि कोई भी लक्ष्य इंडियन एयरफोर्स की पहुंच से दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर 1200 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में और 200 किलोमीटर भीतर तक भारतीय वायुसेना ने सटीक हमले किए, इसने यह साबित कर दिया कि कोई भी लक्ष्य उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। वायुसेना प्रमुख की इस टिप्पणी को पाकिस्तान के लिए चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन



सिंदूर ने वायुसेना के क्षमता-केंद्रित दृष्टिकोण की पुष्टि की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस अभियान ने किसी भी संकट में सबसे पहले कार्रवाई करने वाली शक्ति और दुश्मन को हमला करने से रोकने की प्रभावी सैन्य क्षमता के रूप में वायुसेना की निर्णायक भूमिका की एक बार फिर पुष्टि की है।

हालांकि, वायुसेना प्रमुख ने आगाह किया कि एयरफोर्स के इस दृष्टिकोण की पुष्टि होने का मतलब यह नहीं है कि हम यहीं रुक जाएं। हमें अपनी क्षमताओं को और मजबूत करने तथा उनका विस्तार करने की जरूरत है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि सैन्य अभियान के स्तर पर यह सीख सबसे अहम है कि हमें हमेशा अपने पास कई विकल्प रखने चाहिएं। दुश्मन के अपनी रणनीति बदलने पर तेजी से उसके अनुसार खुद को ढालने की क्षमता बनाए रखनी चाहिए।

ड्रोन से मिसाइल तक मेड इन इंडिया

रक्षा क्षेत्र के दूसरे चरण में भारत का होगा दबदबा, रोडमैप हो गया तैयार



एजेन्सी, नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने के भारत के प्रयास अब दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस कोशिश में इनोवेटर्स इम्पैक्ट प्लेयर्स की भूमिका निभाएंगे।

यहां भारतीय नौसेना के वार्षिक सेमिनार 'स्वावलंबन 2026' के पूर्ण सत्र में अपने संबोधन के दौरान, उन्होंने उन विशिष्ट क्षेत्रों के लिए एक रोडमैप तैयार करने का सुझाव दिया जहां आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है, साथ ही इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय-सीमा तय करने की बात भी कही।

नौसेना मानेकशॉ सेंटर में अपने प्रमुख सेमिनार के पांचवें संस्करण का आयोजन कर रही है। मंच पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि, सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन भी मौजूद थे।

रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में, इस क्षेत्र ने अपने पहले चरण में अच्छे अंक हासिल किए हैं। अब यह दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' के इस अगले चरण में, ऐसे परिणाम देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जो उच्चतम स्तर के हों और अत्याधुनिक (स्टेट-ऑफ-द-आर्ट) हों।

उत्तर प्रदेश प्रदेश कार्यसमिति-2026 का गठन

भाजपा ने जारी की 548 सदस्यीय प्रदेश कार्यसमिति की सूची, पूर्व अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी भी शामिल

एजेन्सी, लखनऊ

भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश कार्यसमिति-2026 के सदस्यों की सूची जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से जारी सूची में 548 कार्यसमिति सदस्य और 30 स्थायी आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। यह घोषणा 30 और 31 अक्तूबर को लखनऊ में होने वाली प्रदेश कार्यसमिति की बैठक से पहले की गई है।

बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इसमें मिशन-2027 के तहत संगठनात्मक तैयारियों और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस कमेटी में स्थायी आमंत्रित सदस्यों की घोषणा कर दी है,



जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कुल 30 प्रमुख नेताओं को स्थान दिया गया है। इस सूची में दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी शामिल हैं। संगठन से जुड़े राष्ट्रीय पदाधिकारियों में रेखा वर्मा, तारिक मंसूर, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, भोला सिंह, संगीता यादव, अमरपाल मौर्य और कुँवर बासित अली को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।

इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों में हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, कमलेश पासवान, जितिन प्रसाद, एस०पी० सिंह बघेल और कीर्तिवर्धन सिंह के नाम सूची में दर्ज हैं। वरिष्ठ नेताओं तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्षों में मुरली मनोहर जोशी, ओमप्रकाश सिंह, विनय कटियार, रमापति राम त्रिपाठी, सूर्य प्रताप शाही, लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, महेन्द्र नाथ पाण्डेय, स्वतंत्र देव सिंह, भूपेन्द्र सिंह चौधरी, साध्वी निरंजन ज्योति और मुख्तार अब्बास नकवी को इस समिति में जगह दी गई है।

548 सदस्यों वाली मुख्य सूची में पश्चिम, बृज, गोरखपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों और जिलों के नेताओं को शामिल किया गया है। पश्चिम क्षेत्र के बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, रामपुर, शामली, संभल, सहारनपुर, नोएडा आदि शामिल है।

100% एथेनॉल वाले ईंधन को सरकार की मंजूरी

सरकार बोली- कच्चे तेल का आयात और प्रदूषण घटेगा

एजेन्सी, नई दिल्ली

भारत में जल्द ही ऐसी कारें सड़कों पर दौड़ती दिखेंगी, जो न तो पेट्रोल-डीजल और CNG से चलेंगी और न ही उनमें बैटरी होगी। केंद्र सरकार ने 100% एथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इसे सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिन्हें कंपनी ने खासतौर पर ए100 फ्यूल से चलने के लिए बनाया हो। नए नियमों से ऐसी कारों की टेस्टिंग और उन्हें चलाने की मंजूरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

सरकार ने फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स को लेकर क्या नया फैसला लिया है?

केंद्र सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में बदलाव करते हुए 100% एथेनॉल यानी ए100 फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को मंजूरी दी है। नए नोटिफिकेशन के तहत एमिशन प्रोविजन में



ए85 फ्यूल के साथ अब ए100 को भी शामिल कर लिया गया है।

E100 फ्यूल क्या होता है और यह कैसे बनता है?

E100 का मतलब 100% शुद्ध एथेनॉल फ्यूल है। एथेनॉल मुख्य रूप से पौधों और बायोलॉजिकल सोर्स जैसे गन्ना और मक्का से तैयार किया जाने वाला एक बायोफ्यूल है। इसमें पेट्रोल की मिलावट नहीं होती। सरकार ने स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल या सामान्य पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां E85 या E100 फ्यूल पर नहीं चल सकती हैं। E85 और E100 फ्यूल का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में हो सकता है जो इसके लिए खास तौर पर डिजाइन और सर्टिफाइड की गई हों।

सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया, कहा- फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया

चुनाव आयोग बोला-एसआईआर पर सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए

एजेन्सी, नई दिल्ली

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच विवाद तेज हो गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 15 बिंदुओं वाला जवाबी हलफनामा दाखिल कर अपनी प्रक्रिया और फैसलों का बचाव किया। आयोग ने मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोपों को खारिज करते हुए याचिका के आधार पर भी सवाल उठाए। आयोग का कहना है कि याचिका एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी ने इस हलफनामे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी।

क्या है यह पूरा मामला?

यह मामला राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं की याचिका से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया था। याचिकाकताओं ने एसआईआर से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने, मतदाता सूची से हटाए गए नामों का स्वतंत्र ऑडिट कराने और बूथवार सूची उपलब्ध कराने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि किसी योग्य मतदाता का नाम बिना सूचना दिए और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना नहीं हटाया जाना चाहिए। आयोग ने अपने जवाब में निर्णय लेने की प्रक्रिया, फॉर्म-6, मतदाता सूची और डिजिटल डेटाबेस को लेकर उठाए गए सवालों पर सफाई दी है।

हलफनामे को सर्वसम्मति से मंजूरी... मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी ने जवाबी हलफनामे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी।

एसआईआर के तीनों आदेश सर्वसम्मति से पारित... आयोग ने कहा कि जून 2025, अक्तूबर 2025 और मई 2026 में एसआईआर को लेकर जारी



तीनों आदेश आयोग के सर्वसम्मत फैसले थे।

फाइलों पर टिप्पणियां अंतिम फैसला नहीं... आयोग के अनुसार, किसी फाइल पर मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की ओर से लिखे गए सवाल, सुझाव या टिप्पणियों को आयोग का अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता।

फाइल मंजूरी की प्रक्रिया... सामान्य तौर पर फाइल पहले एक चुनाव आयुक्त, फिर दूसरे चुनाव आयुक्त और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाती है। तत्काल मामलों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंजूरी ली जा सकती है और बाद में उसे फाइल में दर्ज किया जाता है।

अधिकारों से बाहर आदेश देने पर कार्रवाई... आयोग ने कहा कि अगर कोई अधिकारी उसे सौंपे गए अधिकारों से बाहर जाकर आदेश जारी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

28 जुलाई के कार्य आवंटन आदेश पर सफाई... आयोग ने बताया कि 28 जुलाई का कार्य आवंटन आदेश प्रतिनियुक्ति पर आए एक अतिरिक्त सचिव ने जारी किया था। दोनों चुनाव आयुक्तों ने अगले दिन कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था। आयोग के संयुक्त निर्देश के बाद 30 जुलाई को यह आदेश लागू नहीं किया गया।

फॉर्म-6 में बदलाव नहीं हुआ... आयोग ने कहा कि मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। आयोग के अनुसार, इसमें बदलाव करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।

एसआईआर का घोषणा पत्र अलग दस्तावेज... आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर के लिए इस्तेमाल होने वाला घोषणा पत्र फॉर्म-6 से अलग है। हालांकि, ऑनलाइन आवेदन में इसे दिखाने के तरीके से फॉर्म में बदलाव होने का भ्रम पैदा हो सकता था।

ऑनलाइन आवेदन में बदलाव... आयोग ने कहा कि 21 अक्तूबर से ऑनलाइन आवेदन को फॉर्म-6 और घोषणा पत्र के रूप में अलग-अलग दिखाने की व्यवस्था की जाएगी, जैसा कागजी फॉर्म में होता है।

रिकॉर्ड नहीं मिलने वाले मतदाताओं की सुनवाई... आयोग के मुताबिक, जिन मतदाताओं का रिकॉर्ड पुराने दस्तावेजों से नहीं जुड़ पाया है, उन्हें सामान्य तौर पर सुनवाई के लिए बुलाने की जरूरत नहीं होगी। बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर दस्तावेज जुटाएंगे। विशेष मामलों में सुनवाई होगी और जहां संभव होगा, ऑनलाइन व्यवस्था अपनाई जाएगी।

नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता को मिला नया मंच, निवेशकों के समक्ष युवाओं ने प्रस्तुत किए अभिनव विचार

मंगला यतन यूनिवर्सिटी में दो दिवसीय आइडियाथॉन एवं आंत्रप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026 का भव्य आयोजन



एक सत बुलेटिन, जबलपुर

मंगलायतन यूनिवर्सिटी, जबलपुर में 23 एवं 24 अक्टूबर 2026 को दो दिवसीय 'आइडियाथॉन कॉन्फ्रेंस एवं आंत्रप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026' का भव्य आयोजन किया गया। 'बिल्डिंग फ्यूचर एंटरप्राइजेज' थीम पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों, उद्योगपतियों, निवेशकों, स्टार्टअप विशेषज्ञों एवं युवा उद्यमियों ने सहभागिता की। आयोजन का मुख्य उद्देश्य नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हुए युवाओं के विचारों को सफल व्यावसायिक उद्यमों में परिवर्तित करना रहा। कार्यक्रम के प्रथम दिवस का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। मुख्य अतिथि प्रो. अलकेश चतुर्वेदी, अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. डॉ. चिंता सुधाकर ने शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग के समन्वय पर बल दिया। कुलसचिव प्रो. बी. एस. नागाकिशोर ने युवाओं को नौकरी देने वाला बनने के लिए प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि श्री श्याम मोहन शर्मा, सीओओ, सार्थक आईटी ने तकनीक आधारित स्टार्टअप की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। प्रो. डॉ. तारचंद बेलजी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ने वास्तविक समस्याओं के समाधान आधारित नवाचार को आवश्यक बताया। प्रथम दिवस पर प्रतिभागियों ने अपने स्टार्टअप आइडिया, बिजनेस मॉडल, शोधपत्र एवं केस स्टडी प्रस्तुत किए। विशेषज्ञों ने विचारों की मौलिकता, व्यावहारिकता एवं बाजार की संभावनाओं का मूल्यांकन किया। स्टार्टअप प्रदर्शनी, मेंटरिंग सत्र एवं एमएसएमई योजनाओं पर मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर 'बिल्डिंग फ्यूचर एंटरप्राइजेज' शीर्षक से संपादित पुस्तक का विमोचन किया गया। द्वितीय दिवस पर आयोजित 'निवेश एवं उद्यमिता दिवस' में मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों के रूप में डीआईजी डॉ. विशद तिवारी, एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक श्री अनिल कुमार राठौर (आईएएस), विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. अखिलेश कुमार पांडेय, अपर आयुक्त श्रीमती अंजू सिंह एवं डीटीआईसी के संयुक्त निदेशक श्री विनीत रजक उपस्थित रहे। अतिथियों ने युवाओं को स्वरोजगार, नवाचार, औद्योगिक विकास एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। निवेशक एवं उद्योग विशेषज्ञ पैनल में जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री प्रेम दुबे ने व्यावसायिक नेटवर्किंग के महत्व पर बल दिया। रेडिएंस के निदेशक श्री सुबोध जैन ने स्टार्टअप में निवेश की संभावनाओं पर मार्गदर्शन दिया। एफआईसीसीआई-सीएमएसएमई मध्यप्रदेश के चेयरमैन श्री प्रदीप करंबेलकर ने एमएसएमई और उद्यमिता विकास पर विचार रखे। श्री अखिलेश उपाध्याय ने नवाचार को व्यावसायिक सफलता में बदलने पर जोर दिया। सुश्री प्रीति चौधरी ने स्टार्टअप विकास और फंडिंग पर मार्गदर्शन दिया। श्री अंकित रजक ने उद्यमिता और व्यावहारिक बिजनेस मॉडल पर अनुभव साझा किए। इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक श्री अरुण कुमार पटेल, श्री कैलाश भाटी, श्रीमती मेघना महाजन, खाद्य उद्यमी श्री विवेक त्रिपाठी, गोदरेज के श्री सुदीप अस्थाना, उमरिया डुंगरिया इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मुनीन्द्र मिश्रा एवं शाह मेटल इंडस्ट्रीज के श्री राजीव शाह सहित अनेक उद्योग विशेषज्ञों ने सहभागिता की। ग्रैंड फिनाले में चयनित प्रतिभागियों ने निवेशकों के समक्ष अपने अभिनव स्टार्टअप आइडिया प्रस्तुत किए। उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सर्वश्रेष्ठ आइडिएशन, सर्वश्रेष्ठ बिजनेस मॉडल, सर्वश्रेष्ठ सोशल इनोवेशन, सर्वश्रेष्ठ रिसर्च पेपर/केस स्टडी एवं सर्वश्रेष्ठ इम्प्लुएंसर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। निवेशक-उद्यमी संवाद के माध्यम से प्रतिभागियों को फंडिंग, इनक्यूबेशन, उद्योग सहयोग एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के 'रिसर्च-टू-स्टार्टअप' मॉडल के अंतर्गत आयोजित इस कॉन्क्लेव ने शिक्षा, अनुसंधान, उद्योग एवं निवेश के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम की रूपरेखा सहसंयोजक डॉ. स्वाति सक्सेना ने प्रस्तुत की। संचालन डॉ. एंजेल रूथ एवं आभार प्रदर्शन संयोजक डॉ. वंदना तिवारी ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के एकेडमिक डीन प्रो. राजेश शुक्ला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल की निदेशक प्रो. एम. वसुजा देवी, प्रशासनिक निदेशक डॉ. आशुतोष सक्सेना, प्रो. विकास पांडे, प्रो. एस.पी. तिवारी, कृषि संकाय के डीन प्रो. एस.एस. शुक्ला, प्रो. नीरज राय, डॉ. शिवाकांत प्रजापति, डॉ. मनोज झारिया, डॉ. दिनेश मिश्रा, प्रो. योगेश दुबे, प्रो. पी. कुमार, श्री विनीत जैन, वरिष्ठ प्रबंधक विपणन, ब्रांडिंग एवं प्रवेश श्री रूपल ज्योतिषी सहित विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, अधिकारी, बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

स्टेशन के प्रवेश द्वार में वाहनों की अवैध पार्किंग, बने अवरोध से यात्री होते परेशान

एक सत बुलेटिन, सिहोरा



पश्चिम मध्य रेल जबलपुर जोन का सिहोरा रोड स्टेशन यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना है स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार में दो पहिया चार पहिया वाहनों की अवैध पार्किंग होने से प्रवेश द्वार में अवरोध खड़ा हो जाता है और स्टेशन जाने वाले बाहर निकलने वाली यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दहकार ने स्टेशन प्रबंधक को दी अपनी शिकायत में बताया की सिहोरा रोड स्टेशन में वहां की बेहतर पार्किंग व्यवस्था होने के बावजूद स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्री जिनमें स्टाफ ओर जो यात्री छोड़ने आते है अपने वाहन का पार्किंग किराया बढ़ाने स्टेशन आए अपने वाहन स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार में खड़ा कर चले जाते हैं स्टेशन में दिनभर वहां खड़े रहने से वह यात्रियों के लिए अवरोध का कारण बनते हैं। सिहोरा रोड स्टेशन जबलपुर कटनी जिले में ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टेशन स्टेशन से जबलपुर जिले की सिहोरा मझौली कटनी जिले की बहोरीबंद ढीमरखेड़ा विधानसभा के 1000 से अधिक ग्रामों के ग्रामीण स्टेशन से अपने गंतव्य स्थान की यात्रा करने के लिए सिहोरा रोड स्टेशन पर आश्रित है इसकी इसी महत्वपूर्ण के चलते रेल प्रशासन ने सिहोरा रोड स्टेशन को आदर्श स्टेशन का गौरव प्रदान किया इसके बाद भारत सरकार ने देश के रेल स्टेशनों के सुधारने के लिए शुरू की गई अमृत योजना में सिहोरा रोड स्टेशन को शामिल कर इसके विस्तार और दोनों जिले के यात्री सुविधा बढ़ाने अनेक कार्य शुरू किए गए हैं बावजूद इसके स्टेशन में मुख्य प्रवेश द्वार में वाहनों के कारण बना अवरोध यात्रियों की परेशानी बना है

माता महाकाली का जलवा अलग ही रहा

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में देरी न करें: कलेक्टर



एक सत बुलेटिन, जबलपुर

कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने सीएम हेल्पलाइन में लंबे समय से लंबित शिकायतों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में स्वामित्व योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्वामित्व योजना के तहत प्रत्येक तहसील में एक हजार रजिस्ट्रियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के साथ लंबित शिकायतों के निराकरण पर भी विशेष ध्यान दें। बैठक में अपर कलेक्टर नीता राठौर, रविशंकर राय, शैलेंद्र सिंह, अखिलेश सिंह और सभी एसडीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

कार्यकर्ता अभी से चुनाव तैयारी में जुटे प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ता से आवाहन



एक सत बुलेटिन, सिहोरा

चुनाव तैयारी में कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से आवाहन है कि वह अभी से चुनाव तैयारी में जुट जाए और पंचायत नगरीय चुनाव में पार्टी को सफलता दिलाये इस सफलता का पूरा लाभ आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा यह बात मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उनके स्वागत में पहुंचे सिहोरा विधानसभा के पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से कही राज्यसभा सदस्य प्रतिनिधि पूर्व प्रदेश सचिव बाबा कुरैशी की अगुवाई जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर ग्रामीण उपाध्यक्ष मंजू मिश्रा के संयोजन में गए प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेश चौबे जिला महासचिव अमोल चौरसिया पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर आरके यादव ब्लॉक अध्यक्ष बिहारी पटेल नगर अध्यक्ष पवन सोनी ग्रामीण महिला जिला अध्यक्ष माधुरी जैन प्रभात कुरिया मनीष शुक्ला मनीष खंपरिया नवनीत शुक्ला शेख साबिर फैज आलम शाह अकरम अंसारी पार्षद प्रवीण यादव प्रशांत जैन रघुवीर ठाकुर राजेश हल्दकार सुरेश पटेल के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल थे।

1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली

वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान को बूथ स्तर तक ले जाएगी कांग्रेस

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

मतदाता सूची की शुद्धता, पात्र नागरिकों के मताधिकार की रक्षा और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कांग्रेस ने 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान को देशव्यापी स्तर पर व्यापक रूप देने की तैयारी शुरू कर दी है। अभियान के तहत एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश से लेकर जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय कर मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों को सामने लाने की कार्ययोजना बनाई गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मप्र प्रभारी सांसद कल्याण काले ने यहां पत्रकारों से चर्चा कर बताया कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश द्वारा घोषित इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता घर-घर संपर्क कर मतदाता सूचियों की जांच करेंगे। कांग्रेस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार 143 मतदाता पंजीकृत थे। प्रारूप मतदाता सूची में यह संख्या घटकर 5 करोड़ 31 लाख 31 हजार 983 रह गई, जबकि अंतिम मतदाता सूची में 5 करोड़ 39 लाख 81



हजार 65 मतदाता दर्ज किए गए। पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कुल 34 लाख 25 हजार 78 नाम हटाए जाने की जानकारी दी गई है। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिला कांग्रेस अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, ब्लॉक अध्यक्षों और बूथ स्तर के प्रतिनिधियों के बीच समन्वय स्थापित करेगी। 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक गांवों में चौपाल, घर-घर संपर्क और संगठनात्मक बैठकों के माध्यम से मतदाता सूचियों की जांच की जाएगी। श्री काले ने बताया कि कांग्रेस की प्रस्तावित महारैली में विशेष गहन पुनरीक्षण, मतदाता सूची में पारदर्शिता, पात्र नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा और निर्वाचन आयोग की जवाबदेही जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। अभियान के अगले चरण में संविधान दिवस के अवसर पर 25 और 26 नवंबर को 'दिल्ली चलो' कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके तहत मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 25 नवंबर को ग्वालियर में एकत्रित करने और 26 नवंबर को दिल्ली के लिए रवाना करने की तैयारी है। कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा और यात्रा संबंधी व्यवस्थाएं पार्टी के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार तय की जाएंगी। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा, ग्रामीण अध्यक्ष संजय यादव, विधायक लखन घनघोरिया, पूर्व विधायक विनय सक्सेना, नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, आदि उपस्थित थे।

न्यूज ब्रीफ

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 500 से 900 रुपये में बिक रहीं कार्बाइड और पोटाश गन

ग्वालियर। दीपावली पर बच्चों और लोगों की आंखों की रोशनी छीनने वाली कार्बाइड गन को लेकर ग्वालियर में शासन से लेकर जिला प्रशासन तक सख्ती के निर्देश दिए गए। प्रतिबंध के बाद ग्वालियर में पुलिस और प्रशासन की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की हैं। लगातार अलग-अलग ठिकानों पर दबिश देकर कारखाना से लेकर बेचने वाले तक पकड़े गए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कार्बाइड गन की ऑनलाइन बिक्री है। कार्बाइड गन ऑनलाइन धड़ल्ले से बिक रही हैं। विभिन्न ई-कामर्स कंपनियों की वेबसाइट से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और इंटरनेट मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर महज 500 से 900 रुपये में बिक रही है। यहां बता दें कि 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के कलेक्टरों, कमिश्नरों और पुलिस अधिकारियों को कार्बाइड गन व कार्बाइड लैंप के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने भी धारा 163 के तहत कार्बाइड-पोटाश गन को लेकर आदेश जारी किए। इसमें इनके उपयोग, भंडारण, निर्माण और बेचने पर रोक लगाई है।

मानपुर फेस-1 मल्टी पर 38 लाख रुपये का जलकर बकाया, कटेगा पानी का कनेक्शन

ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर ने बकाएदारों से जलकर की वसूली के लिए अपना अभियान तेज कर दिया है। शहर में बड़े बकाएदारों से राजस्व वसूलने के लिए जहां एक ओर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं और डोर-टू-डोर संपर्क किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। रविवार को वार्ड क्रमांक पांच स्थित मानपुर में नगर निगम की टीम ने लाउडस्पीकर से मुनादी करवाकर बकाएदारों को समय पर टैक्स जमा करने की अंतिम चेतावनी दी। नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी के निर्देशों के परिपालन में चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए कार्यपालन यंत्री रामसेवक शाक्य ने बताया कि मानपुर फेस-1 मल्टी पर जलकर की 38 लाख की राशि बकाया है। नगर निगम द्वारा संबंधित उपभोक्ताओं को 27 अक्टूबर तक बकाया राशि जमा करने की मोहलत दी। कार्यपालन यंत्री ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि तय सीमा 27 अक्टूबर तक बकाया जलकर जमा नहीं किया गया, तो 28 अक्टूबर से मानपुर फेस-1 मल्टी का पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा और जलप्रदाय पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

करवाचौथ से ठीक पहले नवविवाहिता ने खाया जहर: ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप

ग्वालियर। उपनगर ग्वालियर क्षेत्र में एक नवविवाहिता द्वारा जहरीला पदार्थ निगलने का मामला सामने आया है। शादी के महज नौ महीने और अपनी पहली करवाचौथ के ठीक पहले महिला के इस कदम से इलाके में सनसनी फैल गई है। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है।उपनगर ग्वालियर निवासी आरती वर्मा की शादी नौ महीने पहले राहुल वर्मा के साथ हुई थी। हाल ही में आने वाले करवाचौथ के पर्व से पहले महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पता चला कि उसने जहरीला पदार्थ खा लिया है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

शीतला माता मंदिर हादसा मामले में मजिस्ट्रियल जांच तेज, तीन दिन आम लोग दे सकेंगे साक्ष्य

ग्वालियर। शीतला माता मंदिर पर हुए भीषण हादसे को लेकर पुलिस से रिकॉर्ड आने के बाद अब जांच आगे बढ़ी है। सोमवार से तीन दिन तक कोई भी इस मामले में साक्ष्य या जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के बाद पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के बयान होंगे जो इस घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं। जिन पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी थी उन्हें एडीएम कार्यालय बुलवाया जाएगा। वहीं इस मामले में हादसे का फुटेज पुलिस की ओर से पेन ड्राइव के रूप में प्रशासन को मिल गया है। तीन दिन जो साक्ष्य व जानकारी के लिए तय किए गए हैं इसमें प्रशासन को महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की भी संभावना है।

कई संस्थानों ने खत्म किए कोर्स

जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध 50 से अधिक प्राइवेट कॉलेज दो साल में बंद

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर।

जीवाजी विश्वविद्यालय के संबद्ध करीब 50 निजी महाविद्यालय पिछले दो सालों में बंद हो चुके हैं। इसकी वजह नए नियम, विभिन्न अनियमितताओं को लेकर इओडब्ल्यू जैसे संगठन की जांच में आने , नियमों को ताक पर रखना, और छात्रों का प्रवेश न लेना हैं। इसके साथ ही मान्यता नवीनीकरण की फीस अधिक होना और उसके मुकाबले कॉलेज में छात्र संख्या कम होने व कॉलेज संचालकों द्वारा छात्रों को पास न करा पाना भी है। इसके साथ ही कई कॉलेजों ने अपने यहां चलने वाले कोर्स व संकायों को भी बंद कर दिया है। केवल परंपरागत विषयों को ही पढ़ा रहे हैं। इससे शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव आ रहा है यहां बता दें कि जीवाजी विश्वविद्यालय से दो साल पहले करीब 300 प्रायवेट कॉलेज संबद्ध थे। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या अब 250 रह गई है। 42 कॉलेजों की संबद्धता तो एक साथ खत्म की गई थी। कागजों पर चल रहे हवा-हवाई कॉलेजों का पर्दाफाश पिछले दिनों सामने आया कि बंद हुए कॉलेजों में से कुछ धरातल पर संचालित ही नहीं हो रहे थे, बल्कि केवल कागजों और फर्जी दस्तावेजों



के दम पर चल रहे थे। मुरैना और आसपास के अंचलों में संचालित शिवशक्ति महाविद्यालय जैसे चर्चित मामलों के सामने आने के बाद यह खुलासा हुआ कि किस तरह बिना किसी बुनियादी ढांचे, भवन, प्रयोगशाला और योग्य स्टाफ के महाविद्यालयों को मान्यता दी जा रही थी। जब इन संस्थानों की पोल खुली, जिसके परिणामस्वरूप इन्हें बंद करने की कार्रवाई की गई। विश्वविद्यालय सूत्रों और जांच एजेंसियों के अनुसार इन बंद हुए कॉलेजों का मुख्य उद्देश्य केवल शासकीय योजनाओं का लाभ उठाना था। इन संस्थानों द्वारा बिना कक्षाएं लगाए फर्जी विद्यार्थियों के प्रवेश दिखाए जाते थे और इसके आधार पर भारी-भरकम छात्रवृत्ति तथा सरकारी अनुदानों का गबन किया जाता था।

विश्वविद्यालय और विनियामक मानकों की अनदेखी

यूजीसी, उच्च शिक्षा विभाग और संबद्ध विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों का पालन न करने वाले संस्थानों पर भी गाज गिरी है। ऑल इंडिया सर्वे आन हायर एजुकेशन पोर्टल पर सही आंकड़े समय पर अपडेट न करने और निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाई जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन पर शिकंजा कसा। ग्वालियर चंबल में दो साल पहले निजी कॉलेज अपने यहां छात्रों को पास कराने की गारंटी के साथ प्रवेश देते थे। लेकिन सख्ती बढ़ने व परीक्षा केंद्रों के बदलने की वजह से कालेज संचालक अपनी गारंटी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में छात्रों ने कॉलेजों में प्रवेश लेना बंद कर दिया, बल्कि ऐसे कालेजों को चुनना शुरू कर दिया जिनमें पढ़ाई होती है। इस वजह से न केवल कालेज बंद हुए, बल्कि वर्तमान में सौ से अधिक कॉलेजों ने अपने यहां चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों को भी बंद कर दिया। पिछले दो साल में जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध करीब 50 कालेज बंद हुए हैं। इनमें कई मान्यता के नियमों व शर्तों का पालन न करने की वजह से बंद हुए हैं। कुछ के छात्रों के प्रवेश न लेने की वजह से। कई कॉलेजों ने अपने यहां चल रहे पाठ्यक्रमों को भी बंद कर दिया है।

कृषि दलों ने 10 दुकानों का किया औचक निरीक्षण, ई-टोकन व्यवस्था का लिया जायजा



एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

जिले के किसानों को राज्य शासन द्वारा लागू की गई ई-टोकन व्यवस्था के तहत पूरी पारदर्शिता और सुगमता संग गुणवत्तायुक्त खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। कृषि विभाग के दलों ने रविवार को ग्वालियर जिले की 10 प्रमुख खाद-बीज दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानों पर उपलब्ध भौतिक स्टाक और पीओएस मशीन के आंकड़ों का बारीकी से मिलान किया गया। कृषि विभाग के उप संचालक भानु प्रकाश शर्मा ने बताया कि विभागीय दलों द्वारा जिले भर में उर्वरक विक्रय केंद्रों की सतत जांच की जा रही है। निरीक्षण के दौरान टीमों ने दुकानों पर पीओएस मशीन में दर्ज डिजिटल स्टाक और गोदामों में मौके पर मौजूद वास्तविक खाद के स्टाक का भौतिक सत्यापन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन खाद विक्रेताओं के स्टाक में अंतर या अनियमितता पाई जाएगी, उनके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रविधानों के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रविवार को अभियान के तहत टीमें ग्वालियर शहरी और ग्रामीण अंचल के कई विक्रय केंद्रों पर अचानक पहुंची। ग्वालियर शहर में गणेश ट्रेडिंग कंपनी मुरार, न्यू गंभीर खाद भंडार मुरार, माठूलाल हरिशंकर गंज मुरार, शिव फर्टिलाइजर लक्ष्मीगंज, साईं कृषि सेवा केंद्र व शीतला खाद बीज भंडार गुड़ी गुढ़ा का नाका का औचक निरीक्षण किया गया।

पराली जलाने पर कलेक्टर सख्त: कृषि विभाग को अब हर रोज देनी होगी कार्रवाई की रिपोर्ट



एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

ग्वालियर व श्योपुर जिले पिछले दो साल में पराली जलाने के मामले में काफी बदनाम रहे हैं। पराली जलाने के मामले में देश भर में टाप टेन जिलों में अव्वल रहे हैं। हालांकि इस बार 15 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक जिले में पराली जलाने मामले में नौ घटनाएं हुई हैं। चूंकि इस बार धान की रोपाई देरी से हुई हैं इसलिए इस बार कटाई भी देरी से हो रही है। इसलिए अभी घटनाएं कम हैं। इसलिए कलेक्टर ने न केवल पराली जलाने से किसानों को रोकने के लिए शनिवार को अनुभाग स्तर पर एसडीएम के नेतृत्व में समितियां बनाई हैं।

आज से देनी होगी प्रतिनिधि रिपोर्ट

कृषि विभाग को सोमवार से रोजाना रिपोर्ट प्रशासन को देनी होगा। रिपोर्ट लिए उप संचालक कृषि को जिम्मेदार बनाया गया है। उप संचालक जिले विभिन्न क्षेत्रों में फील्ड में निगरानी करने वाले कर्मचारियों से रिपोर्ट लेंगे। कर्मचारियों को रोजाना बताना होगा कि उन्होंने कितने किसानों को पराली जलाने से रोका, समझाया और जलाने वाले कितने किसानों पर कार्रवाइयां की। सभी जगह की एक एकजाई रिपोर्ट कलेक्टर को दी जाएगी। 15 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक जिले में पराली जलाने की नौ घटनाएं हुई हैं। लेकिन अभी तक विभाग व उसके कर्मचारी पराली जलाने वाले किसानों की न तो पहचान कर पाए हैं और न ही अभी तक किसानों पर कार्रवाइयां ही हुई हैं। पराली जलाने से रोकने लिए इस सीजन में पहली कार्रवाई भितरवार में एक हार्वेस्टर संचालक पर की गई है। भितरवार गांव खेड़ा टांका में हरदयाल सिंह अपने हार्वेस्टर में बिना स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाए ही धान की कटाई कर रहे थे। मौके पर उन पर कार्रवाई की गई और उन पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि पराली जलाने को लेकर प्रशासन प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के आदेश हैं।

त्योहारों से पहले ग्वालियर पुलिस का बड़ा एक्शन

ग्वालियर पुलिस की कॉम्बिंग गश्त में 207 वारंटी गिरफ्तार, इनामी बदमाश भी पकड़ा

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने और आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए ग्वालियर पुलिस ने रविवार-सोमवार की दरमियानी रात शहर और देहात में कॉम्बिंग गश्त की। इस दौरान पुलिस ने 207 वारंटियों को गिरफ्तार कर उनके वारंट तामील कराए। इनमें 106 स्थाई और 101 गिरफ्तारी वारंट शामिल हैं। साथ ही 133 गुंडों और 129 हिस्ट्रीशीटरों समेत कुल 262 बदमाशों की जांच की गई। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में एक इनामी बदमाश को भी गिरफ्तार किया गया। प्रभारी पुलिस अधीक्षक कुबेर के निर्देश पर हुई कार्रवाई प्रभारी पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवेश सिंह बघेल सहित जिले के राजपत्रित अधिकारियों ने थाना प्रभारियों और पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाला। पुलिस टीमों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पैदल



गश्त कर फरार बदमाशों, वारंटियों और जिला बदर आरोपियों की तलाश की। उनके घरों पर पहुंचकर भी जांच की गई।

प्रतिमा हटाने के लिए काटे घोड़े के पैर, आंग्रे परिवार का आरोप- जयविलास पैलेस ले गए शिवाजी की मूर्ति

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

सिंधिया-आंग्रे परिवार के बीच दशकों से चला आ रहा संपत्ति विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। 9 एकड़ में फैली हिरण्यवन कोठी को लेकर चल रहे विवाद में अब छत्रपति शिवाजी महाराज की करीब 106 साल पुरानी प्रतिमा का मामला भी जुड़ गया है। आंग्रे परिवार ने हाई कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर आरोप लगाया है कि प्रतिमा को हटाने के दौरान घोड़े के पैर तक काट दिए गए और प्रतिमा को जयविलास पैलेस ले जाया गया। परिवार ने प्रतिमा को उसके मूल स्थान पर स्थापित करने और कोठी की पूर्व स्थिति बहाल करने की मांग की है। इस मामले में सोमवार को हाई कोर्ट मे ं सुनवाई होना है। चित्रलेखा आंग्रे और तुलाजी आंग्रे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य के खिलाफ चल रहे मामले में यह आवेदन दिया है। आवेदन में प्रतिमा को हटाए जाने की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए उसकी मूल स्थान पर पुनर्स्थापना की मांग की गई है। आवेदन के अनुसार,

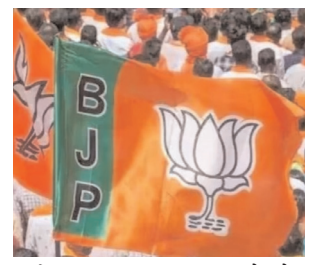


छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार विनायक पी. करमरकर ने किया था। संभाजी राव आंग्रे इसे महाराष्ट्र के अलीबाग से ग्वालियर लेकर आए थे। इसके बाद बसंत विहार और चेतकपुरी के बीच स्थित हिरण्यवन कोठी परिसर में पत्थर के चबूतरे पर प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। आंग्रे परिवार का आरोप है कि प्रतिमा को हटाने के दौरान उसके घोड़े के पैर काटे गए और उसे जयविलास पैलेस ले जाया गया। हिरण्यवन कोठी को लेकर आंग्रे परिवार और सिंधिया पक्ष के बीच कानूनी विवाद करीब चार दशक से अधिक समय से चल रहा है।

भाजपा एससी मोर्चा की ग्वालियर जिला कार्यकारिणी घोषित, जिलाध्यक्ष ने दबाव बनाकर जारी कराई सूची

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ग्वालियर महानगर जिला कार्यकारिणी रविवार की रात को घोषित कर दी गई है। मोर्चा के महानगर जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश धनोल ने जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया की सहमति से पदाधिकारियों की सूची जारी की है। कार्यकारिणी में पांच उपाध्यक्ष, दो महामंत्री और पांच मंत्री सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। युवा, महिला सहित अजा मोर्चा की सूची तैयार हैं, केवल महानगर अध्यक्ष को हटाने की चर्चाओं के चलते अटकी हुई थी।दूसरे दिन ही राजौरिया ने वरिष्ठ नेतृत्व पर दवाब अजा मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित करा दी है। ताकि कार्यकर्ताओं में यह



संदेश जाए कि उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। इसी सप्ताह युवा व महिला मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित कराने के लिए दवाब बनाया जा रहा है।राजा, तुलसीराम, सतीश, रवि और आनंद को बनाया उपाध्यक्ष घोषित सूची के अनुसार, राजा खटीक, तुलसीराम नरवरिया, सतीश खटीक, रवि रांगोड़ी और आनंद आर्य को उपाध्यक्ष बनाया गया है। महामंत्री पद पर दिनेश पारछे व आशी सिंह की नियुक्ति की गई है। इसी तरह रंजीत नरवरे, अनिल माहौर, राकेश नरवरिया, संदीप उमरेठा और सिद्धार्थ (गोल्डी) रत्नाकर को मंत्री नियुक्त किया गया है। वंदना खटीक को भी मंत्री बनाया गया है। मनोज निम को कोषाध्यक्ष, बृजमोहन सखवार और अमृतलाल जाटव को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। नितिन वर्मा को कार्यालय मंत्री, संजय माहुने और किरण सिंह को सह कार्यालय मंत्री बनाया गया है। वहीं, विजय रेंगर को मीडिया प्रभारी तथा सोनू वर्मा और हरेंद्र आर्य को सह मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। कार्यकारिणी के माध्यम से मोर्चा ने महानगर स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए पदाधिकारियों को दायित्व सौंपे हैं।

अमित शाह का ग्वालियर दौरा फिर टला:

साडा में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का भूमिपूजन स्थगित, दिवाली के बाद तय होगी नई तारीख

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

ग्वालियर के साडा क्षेत्र में प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के भूमिपूजन के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का दौरा दूसरी बार टल गया है। 29 अक्टूबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हाथों परियोजना का भूमिपूजन प्रस्तावित था, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। अब दिवाली के बाद नई तारीख तय होने की संभावना है। प्रशासनिक स्तर पर एक-दो दिन में कार्यक्रम की नई प्रस्तावित तिथि सामने आने की उम्मीद है। इससे पहले 12 अक्टूबर को भी भूमिपूजन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन केंद्रीय गृहमंत्री की व्यस्तता के चलते इसे टालना पड़ा था। इस बार भी प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी थीं। एयरपोर्ट से मेला ग्राउंड तक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की जा रही थी। आयोजन की जिम्मेदारी साडा के साथ मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (एमपीएसटीडीसी) को सौंपी गई है। परियोजना के शुरुआती चरण में करीब 2,000 करोड़ रुपये के निवेश और 4,500 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की घोषणा की गई है। भविष्य में इस औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से आठ से नौ हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।



परियोजना के आकार लेने से ग्वालियर को दूरसंचार उपकरण निर्माण के क्षेत्र में नई पहचान मिलने की उम्मीद है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ऐसा विशेष औद्योगिक क्षेत्र होता है, जहां दूरसंचार उपकरणों और उनसे जुड़े कलपुर्जों का निर्माण करने वाली कंपनियों को एक ही स्थान पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यहां मोबाइल फोन, एंटेना, राउटर, ऑप्टिकल फाइबर और 5जी उपकरणों के निर्माण से जुड़ी इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। इससे मुख्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को जरूरी कलपुर्जे स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगे और परिवहन लागत में कमी आएगी। ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, बिजली, पानी, परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसी सुविधाओं की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा, पात्रता और लागू नियमों के अनुसार कंपनियों को केंद्र सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का एक प्रमुख उद्देश्य दूरसंचार उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। देश में 5जी नेटवर्क के विस्तार और भविष्य में 6जी तकनीक की तैयारियों के लिए बड़ी मात्रा में आधुनिक उपकरणों की जरूरत होगी। स्थानीय स्तर पर इनके निर्माण से आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने और लागत कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही, घरेलू कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा।

संपादकीय

विदेशी साजिशों की राजनीति

विदेशी ताकतों की साजिश एक राजनीतिक मुहावरा बन कर रह गया है। यह आज की राजनीति में ही नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी ने भी अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई को सीआईए एजेंट करार दिया था। जब जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब राममनोहर लोहिया सरीखे समाजवादी नेता को भी विदेशी एजेंट करार दिया गया था। भारत में ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ, जिसके कालखंड में विदेशी ताकतों की साजिश और हस्तक्षेप के आरोप न लगाए गए हों। आज सत्तारूढ़ भाजपा यह आरोप नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा) राहुल गांधी पर चस्पां करने में जुटी है। यहां तक बयान दिए गए हैं कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वहां संदिग्ध लोगों से मिलते हैं, उनके साथ साजिशें तैयार करते हैं और फिर भारत लौट कर देश-विरोधी एजेंडा लागू करते हैं।

यह राजनीति मुद्दाहीन, नागरिक समस्याओं और संकटों से विरक्त और देश को स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी इस संदर्भ में एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं लिया, लेकिन एक सार्वजनिक मंच से कहा कि फेल्ड प्रॉडक्ट को लॉन्च करने के लिए कुछ लोग देश की प्रतिष्ठा को ही मिट्टी में मिला देने पर तुले हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कांग्रेस को परजीवी करार दिया और कहा कि कांग्रेस के एक परिवार से ही पाटीर्वाले परेशान और दुखी हैं। कांग्रेस नेता जब अकेले में मिलते हैं, तो वे अपनी पीड़ा और अन्याय बयां करते हैं। आखिर एक ही फेल्ड प्रॉडक्ट को कितनी बार लॉन्च किया जाएगा? इतनी लॉन्चिंग तो श्रीहरिकोटा में भी नहीं होती, जितनी कांग्रेस में एक ही आदमी की हुई है। बेशक प्रधानमंत्री मोदी ने नाम नहीं लिया, लेकिन दुनिया जानती है कि कांग्रेस में वह परिवार और चेहरा कौन है और फेल्ड प्रॉडक्ट किसे कहा जा रहा है? देश में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। राहुल गांधी की राजनीति को अराजक, हंगामाखेज और तोडफोड़ वाली करार दिया जा रहा है।

सवाल है कि यदि राहुल गांधी देश-विरोधी साजिशों और गतिविधियों में संलिप्त हैं, तो उन पर आपराधिक केस दर्ज कर उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। कानूनी फैसला अदालत करेगी। अराजक राजनीति का एक उदाहरण इतिहास में दर्ज होगा, जब मार्च, 1974 में तत्कालीन जनसंघ के युवा नेताओं-सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद-के नेतृत्व में बिहार के राजभवन का घेराव करने की कोशिशें की गईं। मुख्यमंत्री के काफिले का घेराव किया गया, विधानसभा भवन में आग लगाने की कोशिश की गई, विधानसभा सचिव के आवास-दफ्तर का भी घेराव कर तोड़-फोड़ की गई। उस किस्म की राजनीति ने जन-जीवन को भी अस्त-व्यस्त किया। जयप्रकाश नारायण ने उन कोशिशों, कथित आंदोलन या विरोध-प्रदर्शन को क्रांति मानने से इंकार कर दिया था। हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कि क्या वे सड़किया प्रदर्शन अराजक नहीं थे? आज रविशंकर प्रसाद भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं।

सुशील मोदी दिवंगत हो चुके हैं। यदि वह राजनीति अराजक, हंगामेदार नहीं थी, तो कमोबेश राहुल गांधी ने किसी सरकारी आवास, भवन में आग लगाने की न तो कोशिश की है, न ऐसा आह्वान किया है और न ही साजिश रची है। वह सड़किया मार्च के दौरान आकाशवाणी भवन में जरूर घुसे थे, लेकिन एक पेड़ के नीचे धरने पर बैठे रहे, अलबत्ता हम उसे अवैध सेंधमारी मानते हैं। भाजपा और मोदी सरकार के प्रवक्ता आज तक यह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि विदेशी साजिश में कौन-कौन संलिप्त रहा है और किसने, कितनी फंडिंग की है। ले-देकर जॉर्ज सोरोस का नाम ही दोहराया जाता रहा है। दुनिया जानती है कि वह वैचारिक तौर पर भारत के खिलाफ रहा है और भारत-विरोधी बयानबाजी भी करता रहा है। मोदी सरकार ने साढ़े 12 साल के कालखंड में उसे भारत का दुश्मन करार क्यों नहीं दिया? उसके खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की? भारत के एनजीओ को उसकी फंडिंग क्यों नहीं रोकी? क्यों प्रतिबंधित नहीं किया?

देश-विरोधी साजिश, अंततः, देशद्रोह होता है और उसका बाकायदा नया कानून भी मौजूद है।

डिजिटल भारत : बदलती तस्वीर और चुनौतियां

रमेश धवाला

> निस्संदेह डिजिटल इंडिया ने देश में सुविधाओं के नए रास्ते खोले हैं। लेकिन इसकी सफलता का आकलन केवल इंटरनेट उपयोगकताओं, मोबाइल ऐप या ऑनलाइन लेन-देन की बढ़ती संख्या से नहीं किया जा सकता। असली सफलता तब होगी जब किसी दूरस्थ गांव का बुजुर्ग बिना परेशानी अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेगा

भारत में पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल तकनीक ने हमारे दैनिक जीवन को काफी बदल दिया है। कभी बिजली का बिल जमा करने, पैसे भेजने या सरकारी प्रमाणपत्र बनवाने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। आज इनमें से अनेक काम मोबाइल फोन से किए जा सकते हैं। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए डिजिटल इंडिया अभियान ने देश में डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इस बदलाव के साथ एक सवाल भी जुड़ा है कि क्या इन सुविधाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंच रहा है? डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आम नागरिक के लिए सरल और सुलभ बनाना रहा है। आज अनेक प्रमाणपत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। डिजिलॉकर जैसी सुविधाओं ने जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और आवश्यकता पड? पर उपलब्ध कराने का रास्ता आसान किया है। इससे लोगों के समय और पैसे की बचत हुई है। लेकिन कई बार वेबसाइट ठीक से काम नहीं करती या आवेदन लंबे समय तक लंबित रहते हैं।

ऐसी स्थिति में नागरिक को वही परेशानी उठानी पड़ती है जिससे बचाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था बनाई गई थी। इसलिए तकनीक के विस्तार के साथ प्रशासनिक जवाबदेही भी जरूरी है। डिजिटल भुगतान ने भी भारतीय समाज में बड़ा बदलाव लाया है। आज छोटे दुकानदार, सब्जी विक्रेता और रेहड़ी लगाने वाले भी यूपीआई से भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। इससे नकद पैसे रखने की जरूरत कम हुई है और लेन-देन अधिक सुविधाजनक बना है। हालांकि इसके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं ने नई चिंताएं पैदा की हैं। फर्जी संदेश, अनजान लिंक और ओटीपी के माध्यम से ठगी के मामले बताते हैं कि डिजिटल सुविधाओं के साथ लोगों को साइबर सुरक्षा की जानकारी देना भी आवश्यक है। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंचाने की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण कदम है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से बिचौलियों की भूमिका कम करने में सहायता मिली है। फिर भी कुछ लोगों को आधार, बैंक खाते या तकनीकी समस्याओं के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों और कम पढ़े-लिखे नागरिकों के लिए ये प्रक्रियाएं आसान नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सहायता केंद्रों और वैकल्पिक व्यवस्थाओं की भूमिका बढ़ जाती है। किसी पात्र व्यक्ति को केवल तकनीकी समस्या के कारण सरकारी सहायता से वंचित नहीं होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डिजिटल तकनीक की उपयोगिता बढ़ी है। ऑनलाइन कक्षाओं, अध्ययन सामग्री और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने विद्यार्थियों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और डिजिटल रिकॉर्ड से मरीजों को सुविधा मिल सकती है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उद्देश्य पात्र परिवारों को उपचार के खर्च से राहत देना है। लेकिन यह भी समझना होगा कि डिजिटल कार्ड, ऑनलाइन पाठ्यक्रम या प्रमाणपत्र अपने आप बेहतर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी नहीं हैं। इनके लिए अच्छे संस्थान, प्रशिक्षित कर्मचारी और आवश्यक संसाधन भी चाहिए। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में डिजिटल सुविधाओं का महत्व और अधिक है। यहां अनेक गांव जिला मुख्यालयों और सरकारी कार्यालयों से काफी दूर स्थित हैं।

किसी छोटे से काम के लिए भी लोगों को लंबी यात्रा करनी पड़ती है। हिमसेवा और लोकमित्र केंद्रों जैसी व्यवस्थाएं इस दूरी को कम करने में सहायक हो सकती हैं। यदि गांव में ही प्रमाणपत्र, बिल भुगतान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों, तो लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। प्रदेश के पर्यटन और बागवानी क्षेत्रों में भी डिजिटल तकनीक नई संभावनाएं लेकर आई है। छोटे होटल और होमस्टे संचालक ऑनलाइन बुकिंग से पर्यटकों तक पहुंच रहे हैं। बागवान मौसम, मंडी भाव और बाजार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे उनके लिए बेहतर निर्णय लेना संभव होता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या अब भी गंभीर है। कई दूरदराज के गांवों में इंटरनेट की गति इतनी कम होती है कि सामान्य ऑनलाइन आवेदन भरना भी मुश्किल हो जाता है। डिजिटल भारत की एक बड़ी चुनौती समाज में मौजूद डिजिटल असमानता है। शहरों में रहने वाले शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के लिए तकनीक का उपयोग अपेक्षाकृत आसान है। इसके विपरीत गरीब परिवारों, बुजुर्गों और ग्रामीण नागरिकों के सामने अनेक कठिनाइयां हैं। स्मार्टफोन की कीमत, इंटरनेट का खर्च, भाषा की समस्या और तकनीकी जानकारी का अभाव उन्हें पीछे छोड़ सकता है। इसलिए डिजिटल सेवाओं को केवल अंग्रेजी या कठिन प्रशासनिक भाषा तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हिंदी और स्थानीय भाषाओं में सरल निर्देश उपलब्ध कराना भी जरूरी है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा का है। आज बैंक, पहचान और स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत-सी जानकारी डिजिटल माध्यमों में दर्ज होती है।

इसका गलत उपयोग लोगों के लिए गंभीर परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए सरकार और संबंधित संस्थाओं को डेटा सुरक्षा, शिकायत निवारण और साइबर जागरूकता पर लगातार ध्यान देना होगा। लोगों का विश्वास बनाए रखना किसी भी डिजिटल व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है। निस्संदेह डिजिटल इंडिया ने देश में सुविधाओं के नए रास्ते खोले हैं। लेकिन इसकी सफलता का आकलन केवल इंटरनेट उपयोगकताओं, मोबाइल ऐप या ऑनलाइन लेन-देन की बढ़ती संख्या से नहीं किया जा सकता। असली सफलता तब होगी जब किसी दूरस्थ गांव का बुजुर्ग बिना परेशानी अपनी पेंशन प्राप्त कर सके, कोई विद्यार्थी संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे और सामान्य नागरिक को छोटे से छोटे काम के लिए बार-बार सरकारी कार्यालय न जाना पड़े। तकनीक तभी सार्थक है जब वह लोगों का जीवन आसान बनाए।

अमरीका से व्यापार समझौते की उम्मीद

डा. जयंतीलाल भंडारी

ट्रंप काल में शुरू हुई संरक्षणवादी नीतियों, टैरिफ और वीजा पाबंदियों से ठीक पहले तक दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते मुक्त और रणनीतिक सहयोग की मजबूत नींव पर लगातार आगे बढ़ते रहे। ऐसे में अब अमरीका से व्यापार समझौते की संभावनाओं का सुकूनदेह परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहा है। हाल ही में 17 अक्टूबर को अमरीकी प्रशासन द्वारा लींडसे ग्राहम अधिनियम के तहत रूसी तेल खरीददारों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के कठोर फैसले को 60 दिनों के लिए स्थगित करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है। मध्य पूर्व के तनाव और यूक्रेन-रूस संघर्ष से उपजे ऊर्जा संकट के बीच अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत की ऊर्जा जरूरतों और स्त्रोतों के विविधीकरण की सराहना की है।



हाल ही में 21 अक्टूबर को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भारत और अमरीका एक नए व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि दोनों देश समझौता करने के इच्छुक हैं और यह नया सौदा पिछले सभी द्विपक्षीय समझौतों से काफी अलग होगा। ट्रंप का यह बयान अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के हालिया भारत दौरे के दौरान आया। मार्को ने 20 से 22 अक्टूबर के बीच भारत दौरे के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। रुबियो ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के जामनगर संयंत्र का दौरा किया और भारत की इस अनूठी रिफायनिंग क्षमता की सराहना की। रुबियो ने यह भी कहा कि भारत-अमरीकी व्यापार वार्ता अब अंतिम और तकनीकी स्तर पर पहुंच चुकी है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दशकों में वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक मानचित्र पर भारत और अमरीका के संबंध एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक साझेदारी के रूप में उभरे थे, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ये संबंध अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई आर्थिक नीतियों, संरक्षणवादी दृष्टिकोण और सख्त टैरिफ रणनीति के कारण एक चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं।

आज भारत के समक्ष एक तरफ अमरीकी बाजार में अपने मजबूत निर्यात को सुरक्षित रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ रूस से रियायती दरों पर अपनी ऊर्जा जरूरतों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का रणनीतिक संतुलन साधने का दबाव है। इस खींचतान के बीच हालिया अमरीकी नीतिगत फैसले, वीजा नियमों में अत्यधिक सख्ती, जेनेरिक दवाओं पर प्रस्तावित शुल्क की चुनौतियों के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री रुबियो की हालिया सकारात्मक टिप्पणियों से भारत और अमरीका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) एक नई पटकथा के साथ उभरते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद से लेकर 2016 तक भारत और अमरीका के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों में एक प्रभावी दौर देखने को मिला। वर्ष 2000 मैं दोनों देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 6 गुना बढकर अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान अमरीकी बाजार में भारतीय आईटी सेवाओं, फार्मास्युटिकल उत्पादों, कपड़ों और रत्नों की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ, जिससे भारत की आर्थिक साख वैश्विक स्तर पर स्थापित हुई। इस आर्थिक प्रगति को 2008 के ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते और 2016 में भारत को मिले मेजर डिफेंस पार्टनर के दर्जे से गहरा रणनीतिक बल मिला। रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के नए द्वार खुलने के साथ-साथ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी कंपनियों जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो ने अमरीकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान एच-1बी वीजा नीति ने भारतीय कुशल पेशेवरों को अमरीका में कार्य करने और वैश्विक पहचान बनाने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए। निवेश के दृष्टिकोण से भी यह दौर बेहद समृद्ध रहा, जहां 2000 से 2016 के बीच माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जीई, आईबीएम और बोइंग जैसी शीर्ष अमरीकी कंपनियों ने भारत के तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल और रक्षा क्षेत्रों में भारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई किया। साथ ही भारतीय कंपनियों ने भी अमरीकी बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

ट्रंप काल में शुरू हुई संरक्षणवादी नीतियों, टैरिफ और वीजा पाबंदियों से ठीक पहले तक दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते मुक्त और रणनीतिक सहयोग की मजबूत नींव पर लगातार आगे बढ़ते रहे। ऐसे में अब अमरीका से व्यापार समझौते की संभावनाओं का सुकूनदेह परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहा है। हाल ही में 17 अक्टूबर को अमरीकी प्रशासन द्वारा लींडसे ग्राहम अधिनियम के तहत रूसी तेल खरीददारों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के कठोर फैसले को 60 दिनों के लिए स्थगित करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है। मध्य पूर्व के तनाव और यूक्रेन-रूस संघर्ष से उपजे ऊर्जा संकट के बीच अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत की ऊर्जा जरूरतों और स्त्रोतों के विविधीकरण की सराहना की है। रूस से प्रतिस्पर्धी दरों पर कच्चा तेल खरीदने की इस छूट से भारत में ईंधन की लागत नियंत्रित रहेगी और घरेलू बाजार में महंगाई का दबाव कम होगा। इसके साथ ही इस फैसले ने टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग सामान जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों के भारतीय निर्यातकों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अल्पकालिक अनिश्चितता से बचाकर अंतरराष्ट्रीय ऑर्डरों का प्रवाह बनाए रखने में मदद की है। निःसंदेह तेल टैरिफ पर 60 दिनों की राहत के बावजूद, आव्रजन और वीजा नियमों में सख्ती के कारण भारतीय आईटी पेशेवरों, कॉर्पोरेट जगत और चिकित्सा विशेषज्ञों पर संकट गहराता जा रहा है। एच-1बी वीजा पर लगाए गए 1 लाख डॉलर के अतिरिक्त शुल्क को एक वर्ष के लिए बढ़ाने और जांच प्रक्रिया को बेहद सख्त करने से बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों के पंजीकरण में 92 प्रतिशत तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कुल मंजूर एच-1बी वीजा में भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 71 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त नौकरी छूटने के बाद मिलने वाले 60 दिनों के वैधानिक ग्रेस पीरियड को खत्म करने का नया प्रस्ताव भारतीय पेशेवरों के लिए गंभीर संकट खड़ा कर सकता है, क्योंकि नौकरी समाप्त होते ही उनका कानूनी गैर-आप्रवासी दर्जा खत्म हो जाएगा और उन्हें तुरंत अमरीका छोडकर पुनः आवेदन करने की बाध्यता होगी। ऐसे में अमरीका से आर्थिक अनिश्चितता और संरक्षणवाद के इस दौर में भारत को केवल रक्षात्मक रुख अपनाने के बजाय अपने राष्ट्रीय आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए एक दीर्घकालिक और बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। अमरीका और यूरोपीय संघ पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए लैटिन अमरीका, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के गैर-पारंपरिक बाजारों में भारतीय उत्पादों की पैठ बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ लंबित मुक्त व्यापार समझौतों को तेजी से अंतिम रूप देना होगा।

घरेलू स्तर पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं का विस्तार करना होगा और सेवा क्षेत्र को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर तथा उच्च प्रौद्योगिकी की दिशा में अपग्रेड करना होगा ताकि अमरीकी नीतियों के झटकों का प्रभाव न्यूनतम किया जा सके। भारत और अमरीका के बीच जारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ता के तहत भारत को सहयोग और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के बीच एक संतुलित और दृढ़ रुख अपनाना होगा। भारत को कृषि, डेयरी और एमएसएमई जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी क्योंकि इन क्षेत्रों से भारत की विशाल आबादी की आजीविका जुड़ी हुई है।

विशेषज्ञों की नियुक्ति, अस्पताल प्रबंधकों की पदस्थापना, डायलिसिस सेवाओं और मेडिकल कॉलेजों में कैंसर उपचार सुविधाओं के विस्तार पर हुई चर्चा

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं : उप मुख्यमंत्री

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं आमजन की प्राथमिकता से जुड़ा विषय हैं। स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण, उन्नयन, मानव संसाधन की उपलब्धता और चिकित्सा सेवाओं के प्रभावी संचालन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्यों को समय-सीमा में पूरा किया जाए और जहां भी अनावश्यक विलंब पाया जाए, वहां संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास, चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता तथा अस्पतालों के प्रबंधन से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए और जनसामान्य को समय पर सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नवीन एवं उन्नयित स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी गई। बताया गया कि अनुमोदित 71 स्वास्थ्य संस्थानों में 29 नवीन स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं, जिनके प्रशासनिक अनुमोदन जारी हो चुके हैं। इन संस्थानों के निर्माण के लिए शीघ्र टेंडर प्रक्रिया पूरी कर



निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। शेष 42 स्वास्थ्य संस्थानों में उन्नयन कार्य किए जाने हैं। इनमें से 22 संस्थानों के उन्नयन का कार्य पीआईयू तथा 20 संस्थानों के उन्नयन का कार्य मध्यप्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीबीडीसी) द्वारा किया जाना है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्माण एजेंसियों से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समयबद्ध रूप से पूरी की जाएं। निर्माण एवं उन्नयन कार्यों की नियमित निगरानी की जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने एम्बुलेंस सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सेवाओं के प्रदर्शन की सघन मॉनिटरिंग की जाए तथा आवश्यक निगरानी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों को समय पर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध हो सके। सेवा प्रदायगी में होने वाले विलंब और अन्य व्यावहारिक समस्याओं की नियमित समीक्षा करते हुए व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के साथ उनकी समयबद्धता और सुगमता भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए संबंधित अधिकारी सेवाओं के प्रदर्शन पर निरंतर नजर रखें तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएं। बैठक में अस्पताल प्रबंधक पदों पर पदस्थापना से संबंधित कार्यवाही की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अस्पताल प्रबंधकों की काउंसलिंग शीघ्र आयोजित कर पदस्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उपलब्ध मानव संसाधन का प्रभावी उपयोग किया जाए तथा संबंधित प्रक्रियाओं को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। चिकित्सा अधिकारी एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से चयन की कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की विभाग स्तर पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने तथा साक्षात्कार आयोजित करने से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने आवश्यक प्रक्रियाओं को नियमानुसार आगे बढ़ाते हुए चिकित्सकीय मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

मानस भवन में वाल्मीकि जयंती प्रकटोत्सव पर समरसता सम्मेलन आयोजित

महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों से ही मजबूत होगा सामाजिक ताना-बाना: महापौर राय

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

महर्षि वाल्मीकि के विचार और जीवन मूल्य आज भी समाज को एकता, सद्भाव और परस्पर बंधुत्व की प्रेरणा देते हैं। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण संपूर्ण मानवता को सत्य, कर्तव्यनिष्ठा और सामाजिक समरसता का मार्ग दिखाती है। यह बात भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय ने सोमवार को मानस भवन में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा आयोजित वाल्मीकि जयंती प्रकटोत्सव एवं समरसता सम्मेलन में कही। विधायक श्री भगवानदास सबनानी ने वाल्मीकि समाज के सामाजिक सेवा एवं जनकल्याण के क्षेत्र में योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान और जनकल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करने वाले सामाजिक



कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। सम्मेलन में वक्ताओं ने महर्षि वाल्मीकि के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए समाज के सर्वांगीण विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम में समाज सेवा एवं जनकल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वाल्मीकि समाज के 15 सामाजिक कार्यकर्ताओं को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में श्री दिनेश भारती, श्रीमती आशा पारोचे, श्री ब्रजेश टांक, श्री विरेन्द्र धोलपुरे, श्रीमती आरती नरवारे, श्री दुलीचंद ऊंटवाल, श्री जयप्रकाश खरे, श्री संजय डुमाने, बहन छाया वाल्मीकि, बहन गीता वाल्मीकि, बहन वन्दना खरे, बहन रेखा धोलपुरिया, बहन संगीता राजौरिया, बहन अंजना घावरी एवं भाई मुकेश वाल्मीकि शामिल हैं। मानस भवन में आयोजित सम्मेलन में भोपाल एवं आसपास के क्षेत्रों से आए वाल्मीकि समाज के 750 से अधिक नागरिकों और गणमान्यजनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य महर्षि वाल्मीकि के विचारों, आदर्शों और संदेशों को जन-जन तक पहुंचाना तथा समाज में समरसता, समानता, सद्भाव और सामाजिक एकता की भावना को सुदृढ़ करना है।सम्मेलन के माध्यम से सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने, सभी वर्गों के बीच परस्पर सम्मान एवं सहयोग की भावना विकसित करने तथा महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों को आत्मसात करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री पंकज जोशी, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व सदस्य श्री गंगाराम घोषरे, मध्यप्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री सूरज खरे तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग श्री सतेंद्र सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जागरूकता सप्ताह-2026 का शुभारंभ रेलकर्मियों ने ली सत्यनिष्ठा की शपथ



■ एक सत बुलेटिन, **बैरसिया।**

पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल में सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 का शुभारंभ सत्यनिष्ठा की शपथ के साथ किया गया। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर, भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज त्यागी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्य एवं सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने की शपथ दिलाई। मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कार्य दायित्वों का निष्पक्षता से निर्वहन करने का संकल्प लिया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26 अक्टूबर से 01 नवंबर 2026 तक 'सत्यनिष्ठा से समृद्धि' थीम के साथ मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य रेलकर्मियों को अपने कार्यों में ईमानदारी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रति जागरूक करना तथा कार्यप्रणाली में नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करना है। इस दौरान रेलकर्मियों को भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता अपनाने, नियमों का पालन करने तथा रेल सेवाओं में पारदर्शिता एवं जनविश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के माध्यम से रेल प्रशासन का उद्देश्य संगठन में सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देना है, ताकि रेल सेवाओं को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय एवं जनोन्मुखी बनाया जा सके। इस कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक, सभी शाखा अधिकारी सहित बड़ी संख्या में कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मौसम बदलाव और त्योहारों को देखते हुए चिकित्सा व्यवस्थाओं का सीएमएचओ ने किया निरीक्षण

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

आने वाले त्योहारों और मौसम में परिवर्तन को देखते हुए अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. मनीष शर्मा ने जयप्रकाश जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण में आईसीयू,अस्थि रोग, आकस्मिक चिकित्सा इकाई, जनरल ओपीडी, मेडिसिन,शिशु रोग विभाग, श्वसन रोग विभाग की सेवाओं को देखकर सिविल सर्जन को समुचित निर्देश दिए गए। डॉ. शर्मा ने जयप्रकाश जिला चिकित्सालय में बनाए हुए बर्न वार्ड का मुआयना किया। दीपावली को देखते हुए अस्पताल में 5 बिस्तरों का वार्ड बनाया गया है। जो कि विशेष रूप से पटाखों से जलने की दुर्घटनाओं के इलाज के लिए बनाया गया है। सीएमएचओ ने निरीक्षण के दौरान सांस से जुड़ी बीमारियों एवं समस्याओं के लिए ऑक्सीजन सिस्टम, नेबुलाइजर, वेंटिलेटर की क्रियाशीलता एवं दवाइयों की उपलब्धता की जांच की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि शीतकाल एवं अत्यधिक आतिशबाजी से प्रदूषण बढ़ने की संभावना रहती है, इसको देखते हुए अस्पतालों में सभी



आवश्यक तैयारियां को सुनिश्चित किए जाने के संबंध में कहा गया है।

विद्युत आपूर्ति को सुरक्षित बनाए रखने के लिए एमपी ट्रांसको की पहल

रामौआ डैम के बैकवॉटर क्षेत्र से गुजरने वाली 220 केवी लाइन का शिफ्टिंग कार्य पूरा : ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन तोमर

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने ग्वालियर के रामौआ डैम के बैकवॉटर क्षेत्र के समीप से गुजरने वाली महत्वपूर्ण 220 केवी महलगांव (ग्वालियर)-दतिया ट्रांसमिशन लाइन की शिफ्टिंग का कार्य पूरा कर लिया है। पुरानी लाइन डैम के बैकवॉटर क्षेत्र के नजदीक होने के कारण मानसून के दौरान पानी का स्तर बढ़ने पर विद्युत लाइन के कंडक्टर पानी के संपर्क में आने की आशंका रहती थी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए लाइन को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का कार्य किया



गया। सक्रिय पहल से ग्वालियर की विद्युत आपूर्ति सुरक्षित तोमर ने बताया कि एमपी ट्रांसको की इस सक्रिय पहल से मानसून के दौरान जलस्तर बढ़ने के कारण कंडक्टर के पानी के संपर्क में आने से उत्पन्न हो सकने वाले विद्युत व्यवधान की आशंका को दूर करने में मदद मिली है। समय रहते पूरा किया गया यह कार्य ग्वालियर क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को सुरक्षित और निर्बाध बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित ट्रांसमिशन लाइन की विश्वसनीयता भी बढ़ी है। 8 पुराने टावर हटाए, 10 नए टावर स्थापित मध्यप्रदेश के ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस के मुख्य अभियंता श्री दीपक कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कार्य के अंतर्गत पुरानी ट्रांसमिशन लाइन के 8 टावर हटाए गए, जिनसे संबंधित लाइन की लंबाई 2.860 किलोमीटर थी। इसके स्थान पर 10 नए टावर स्थापित कर 3.406 किलोमीटर लंबाई की लाइन तैयार की गई। इस प्रकार लाइन के मार्ग में आवश्यक बदलाव कर उसे डैम के बैकवॉटर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्या से सुरक्षित किया गया।

27 अक्टूबर 2026 से होगी शुरुआत, मात्र 45 पैसे के प्रीमियम पर मिलेगा 10 लाख तक का सुरक्षा कवर

आरक्षण काउंटर से आरक्षित टिकट लेने वाले रेल यात्रियों के लिए 'वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना' का विस्तार

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

भारतीय रेल ने आरक्षण प्रणाली को अधिक यात्री-हितैषी और सुरक्षित बनाते हुए एक बड़ा निर्णय लेते हुए 'वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना' (ह्रश्चह्लद्बश्ठ्ठड्डद्य ञ्जह्ड्ड1द्गद्य ढ्ठठ्ठह्यह्लह्लद्बड्डठ्ठष्द्ग स्द्धद्गद्गद्बद्गद्गद्ग - ह्लञ्जढ्ठह्ल) का विस्तार अब आरक्षण काउंटरों से आरक्षित टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए भी करने का फैसला किया है। यह सुविधा 27 अक्टूबर 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों पर लागू हो जाएगी। अब तक यह सुविधा केवल आईआरसीटीसी माध्यम से ई-टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध थी, जिसे अब ऑफलाइन काउंटर टिकट धारकों के लिए भी समान शर्तों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यात्रियों को मिलने वाले प्रमुख लाभ व कवरेज इस योजना के तहत ट्रेन दुर्घटना अथवा किसी अप्रिय घटना के घटित होने की स्थिति में यात्रियों को निम्नलिखित वित्तीय सुरक्षा व लाभ प्रदान किए जाएंगे: 1. मृत्यु : दुर्घटना अथवा अप्रिय घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में ?10,00,000 (100% बीमित राशि) का भुगतान नामांकित व्यक्ति अथवा कानूनी वारिस को किया जाएगा। 2. स्थायी पूर्ण दिव्यांगता : दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से पूर्ण दिव्यांग होने (जैसे दोनों आंखों की रोशनी जाना, दोनों अंगों की हानि आदि) पर ?10,00,000 (100% बीमित राशि) की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 3. स्थायी आंशिक दिव्यांगता : शरीर के किसी अंग या कार्यक्षमता की स्थायी आंशिक क्षति होने पर तालिका के अनुसार अधिकतम ?7,50,000 (बीमित राशि का 75% तक) का लाभ देय होगा। 4. चोट के इलाज हेतु अस्पताल खर्च : दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल में भर्ती और चिकित्सीय उपचार के लिए ?2,00,000 तक का वास्तविक खर्च प्रदान किया जाएगा। यह कवरेज मृत्यु या दिव्यांगता लाभ के अतिरिक्त होगा। 5. पार्थिव शरीर का परिवहन :



दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में पार्थिव शरीर को मृतक के निवास स्थान या श्मशान/कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए ?10,000 की एकमुश्त सहायता राशि बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य की अनिवार्यता के प्रदान की जाएगी। योजना की प्रमुख विशेषताएं एवं नियम 1. न्यूनतम प्रीमियम: यह विस्तृत सुरक्षा कवर मात्र 45 पैसे (सभी करों सहित) प्रति यात्री के प्रीमियम पर उपलब्ध है। 2. यात्रा की पूरी अवधि में सुरक्षा: बीमा कवर मूल स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान से लेकर गंतव्य स्टेशन पर आगमन तक, जिसमें ट्रेन में चढ़ने और उतरने की प्रक्रिया भी शामिल है, पूर्णतः मान्य रहेगा। 3. मार्ग परिवर्तन / विकल्प ट्रेन में भी मान्य: ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन, यात्रा बीच में समाप्त होने पर रेलवे द्वारा की गई वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था, या 'विकल्प' ट्रेन में भी यह पॉलिसी स्वतः मान्य रहेगी। 4. समान सुरक्षा: यह योजना सभी यात्रा श्रेणियों के लिए समान रूप से लागू है। काउंटर पर बीमा सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया 1. स्वैच्छिक विकल्प: यह योजना पूरी तरह से वैकल्पिक है। यदि किसी पीएनआर पर यह विकल्प चुना जाता है, तो उस पीएनआर के सभी पात्र यात्रियों पर यह लागू होगा। 2. पात्रता: यह सुविधा कन्फर्म, आरएसी और आंशिक कन्फर्म टिकट धारक भारतीय नागरिकों के लिए मान्य है। 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चे भी इसके पात्र हैं। 3. डिजिटल भुगतान व मोबाइल नंबर अनिवार्य: पीआरएस काउंटर पर बीमा का विकल्प चुनने वाले यात्रियों को अपना वैध मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा तथा टिकट किराए एवं प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य होगा। 4. पॉलिसी विवरण व नॉमिनेशन: टिकट जारी होने के बाद पॉलिसी विवरण सीधे यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा। यात्री बीमा कंपनी के वेब पोर्टल पर जाकर अपने नॉमिनी का विवरण दर्ज कर सकेंगे। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है, मात्र 45 पैसे में ?10 लाख तक का यह व्यापक बीमा कवर अप्रिय परिस्थितियों में यात्रियों और उनके परिवारों को मजबूत वित्तीय संबल प्रदान करेगा। पीआरएस काउंटर से आरक्षित टिकट बनवाते समय यात्री अपना सही मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज कराएं और डिजिटल भुगतान कर इस अत्यंत लाभकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।



सर्दियों में खाएं ये फूड्स, हार्ट अटैक का खतरा होगा कम

सर्दियों के मौसम में दिल का खास ख्याल रखना पड़ता है। दरअसल ठंड में हार्ट अटैक के मामले में इजाफा हो जाता है। ठंड के मौसम में ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती है जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। वहीं जिन लोगों की लाइफ स्टाइल पहले से ही खराब होती है उनके दिल पर ज्यादा खतरा होता है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने दिल को सर्दियों में हल्दी बनाए रखें तो हम आपको कुछ खाद्य पदार्थों की जानकारी दे रहे हैं जिसे डाइट में शामिल करने से आपके हार्ट को फायदा होगा बीपी कंट्रोल में रहेगी।

सर्दियों में हार्ट अटैक के खतरे से बचने के लिए आप मछली,संतरा, अखरोट, लहसुन जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं।

अखरोट



सर्दियों के मौसम में आपको ड्राई फ्रूट जैसे अखरोट को डाइट में शामिल करना चाहिए, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, इससे ब्लड वेसेल्स की सेहत बनी रहती है। यह अल्फा लिनोलेनिक एसिड का समृद्ध स्रोत है जो हृदय सेहत में सुधार करते हैं।

आंवला

सर्दियों में आपको विटामिन सी से भरपूर आंवला का सेवन भी करना चाहिए। यह एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भी भरपूर होता है, जो हार्ट हेल्थ को सुधारने में मदद कर सकता है। इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

लहसुन



लहसुन को भी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसमें एलिसिन नामक कंपाउंड होता है, जो ब्लड प्रेशर को कम कर मदद करता है, ब्लड वेसल्स को हेल्दी बनाता है, जिससे दिल की सेहत को सपोर्ट मिलता है। इससे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है।

मछली

अगर आप नॉनवेज लवर हैं तो आपको ठंड में मछली खाना चाहिए। इसमें कार्ब्स की मात्रा कम और ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। यह आपके हार्ट को फायदा पहुंचता है।

संतरा

विटामिन सी से भरपूर संतरे का सेवन जरूर करना चाहिए, यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो दिल की सेहत का ख्याल रखता है। यह बीपी को नियंत्रित करता है, रक्त वाहिकाओं की सेहत बनाए रखता है। विटामिन सी सूजन को कम करता है।





पीसीओएस की समस्या को नेचुरली करना है मैनेज तो फॉलो करें इंटरमिटेंट फास्टिंग

अगर आप पीसीओएस की शिकायत से जूझ रहे हैं तो ऐसे में आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का ऑप्शन चुनना चाहिए। इससे आपको यकीनन फायदा होगा।

आज के समय में अधिकतर महिलाएं पीसीओएस की समस्या से जूझ रही हैं। पीसीओएस की समस्या होने पर ना केवल आपको अधिक वजन के कारण परेशान होना पड़ता है, बल्कि इसके साथ-साथ आपको मूड स्विंग से लेकर अनियमित पीरियड्स जैसी कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि आप पीसीओएस को मैनेज करें और इसका सबसे पहला व बेसिक स्टेप है अपने लाइफस्टाइल को बदलना।

अगर आप भी पिछले काफी समय से पीसीओएस को मैनेज करने की जद्दोजहद में जुटी हैं तो ऐसे में इंटरमिटेंट फास्टिंग करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अक्सर पीसीओएस को मैनेज करने के लिए हम सभी वजन कम करना चाहती हैं और इसके लिए अपने खाने को प्रतिबंधित करती है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके खाने की टाइमिंग पर अधिक फोकस करती है। जिससे इंसुलिन सेंसेटिविटी बेहतर होने से लेकर हार्मोन बैलेंस करने और वजन घटाने में भी मदद मिलती है। जिससे आपको पीसीओएस में काफी फायदा मिलता है। तो चलिए आज इस लेख में सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ईएसआईसी अस्पताल की डाइटीशियन रितु पुरी आपको बता रही हैं कि पीसीओएस की समस्या होने पर इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरह फायदा पहुंचा सकती है-

इंसुलिन सेंसेटिविटी होती है बेहतर

जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करती हैं तो इससे आपकी इंसुलिन सेंसेटिविटी बेहतर होती है। जिससे आपको पीसीओएस में लाभ होता है। दरअसल, पीसीओएस वाली अधिकतर महिलाओं में इंसुलिन का स्तर अधिक होता है। ऐसे में उनके शरीर के लिए ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इससे ना केवल वजन तेजी से बढ़ता है, बल्कि हार्मोनल असंतुलन की शिकायत भी होती है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए जब आप अपने खाने की टाइमिंग को सेट करती हैं तो इससे इंसुलिन लेवल को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है।

हार्मोन होते हैं बैलेंस

पीसीओएस की समस्या होने पर हार्मोन असंतुलित होने लगते हैं। लेकिन जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इससे हार्मोन बैलेंस करने में मदद मिलती है। दरअसल, इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने से आपका वजन धीरे-धीरे कम होने लगता है, जिससे आपके हार्मोन बैलेंस होने लगते हैं। इसके अलावा, इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो इंसुलिन और एण्ड्रोजन के स्तर को कम करते हैं। यह बालों के विकास या मुंहासे जैसे पीसीओएस लक्षणों को कम कर सकता है।

मेटाबॉलिज्म होता है बूस्ट

अक्सर वजन कम करने के लिए लोग क्रैश डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन यह आपको काफी सुस्त महसूस करवाती है। लेकिन जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग पीरियड के दौरान आपका शरीर में पहले से ही स्टोर फैट को एनर्जी में बदलता है। इससे ना केवल आपका वजन कम होता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म भी बूस्टअप होता है। अतिरिक्त भूख होती है नियंत्रित पीसीओएस में आपके भूख से जुड़े हार्मोन ग्रेलिन और लेप्टिन का तालमेल बिगड़ सकता है, जिससे आपको अत्यधिक खाने की इच्छा हो सकती है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग इन भूख हार्मोन को रीसेट करने में मदद कर सकती है, जिससे यह पहचानना आसान हो जाता है कि आपको वास्तव में कब भूख लगी है और कब आपको बस यूं ही क्रेविंग्स हो रही है। इससे जब आप अपनी अतिरिक्त भूख को नियंत्रित कर पाते हैं तो इससे आपकी ओवर ऑल हेल्थ सुधरती है।





शरीर में पोटेशियम का स्तर कम हो जाए तो क्या होगा?

पोटेशियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है यह एक इलेक्ट्रोलाइट्स है जो शरीर को रिचार्ज करता है। सेल्स तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के ठीक से काम करने के लिए पोटेशियम बेहद जरूरी है।

शरीर में पोटेशियम का लेवल बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। कई बार खराब खानपान के चलते इसकी कमी हो जाती है, जिससे सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आइए जानते हैं शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाए तो क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

- पोटेशियम शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जब इसकी कमी होती है तो कोशिकाओं में असंतुलन हो सकता है, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव और अकड़न पैदा हो सकता है।
- पोटेशियम का स्तर कम होने से मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। इससे भ्रम, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी उलझन जैसी समस्याएं हो सकती है।
- इसकी कमी के कारण व्यक्ति थकान और कमजोरी महसूस कर सकता है। सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है।
- पोटेशियम की कमी से व्यक्ति को त्वचा संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, हड्डियों पर भी इसका असर पड़ सकता है।
- पोटेशियम की कमी के चलते हाई ब्लड प्रेशर की समस्या पैदा हो सकती है,जिससे दिल को नुकसान हो सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिल को अधिक काम करना पड़ता है। इसके चलते स्ट्रोक दिल का दौरा जैसी समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। इससे दिल की धड़कन भी सामान्य हो सकती है।





एचएमपीवी से हो सकता है बचाव, पिएं यह सूप

एचएमपीवी वायरस से बचाव के लिए इम्यूनिटी का मजबूत होना बेहद जरूरी है। आप इस खास सूप को पीकर इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं।

सर्दियों में संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं इन दिनों एचएमपीवी जैसे वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यह उन लोगों को अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। खासतौर पर बच्चों बुजुर्ग या जिन लोगों को कोई बीमारी हो। ऐसे में सही खान-पान और पौष्टिक भोजन के जरिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। सूप एक बेहतरीन विकल्प है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। इम्युनिटी बढ़ाने के लिए आप मिक्सड वेज सूप का

मिक्सड वेज सूप बनाने की रेसिपी

1 कप गाजर, ½ कप शिमला मिर्च
1 कप मटर, 1 कप लौकी, आधा कप पालक
1 टमाटर कटा हुआ, 1 प्याज बारीक कटा हुआ
2 से 3 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक
1 तेज पत्ता, 2-3 लौंग, एक चम्मच घी
काली मिर्च पाउडर ½ चम्मच, स्वादानुसार नमक
2 कप पानी

विधि

- सूप बनाने के लिए गाजर, शिमला मिर्च, मटर, लौकी, टमाटर और पालक को अच्छी तरह से धोकर उबाल लें।
- उबली हुई सब्जियों को ठंडा होने के लिए रख दें।
- उसके बाद इसे ब्लेंडर में पीसकर पेस्ट तैयार
- इसमें जीरा, कटा हुआ प्याज, लहसुन अदरक लौंग और तेज पत्ता डालकर भून लें।
- अब इसमें पिसी हुई सब्जियां डालें और अच्छी तरह से मिलाएं ।
- सूप को पतला करने के लिए इसमें पानी डालें और 8 से 10 मिनट तक पकने दें।
- स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च डालें।
- तैयार है आपका मिक्सड वेज सूप चाट मसाला डालें और गरमा-गरम सर्व करें।

मिक्सड वेज सूप के फायदे

- मिक्सड वेज सूप सभी तरह के विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, जब इम्यूनिटी मजबूत होती है तो किसी भी तरह के इंफेक्शन को बढ़ने का खतरा काफी कम हो जाता है, आपका शरीर संक्रमण से लड़ता है।
- वहीं यह सूप पाचन को भी दुरुस्त रखता है। इसके अलावा यह शरीर को गर्माहट देता है।
- इसमें इस्तेमाल अदरक लहसुन और हल्दी जैसे मसाले में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरस गुण होते हैं जो संक्रमण को कम करते हैं। सूप शरीर को हाइड्रेट रखता

हार्वेस्टर संचालकों को स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य

बिना कटिंग मशीन के काम करने वाले हार्वेस्टरों को तत्काल जप्त कर थाने में रखवाने के निर्देश

■ एक सत बुलेटिन, भिण्ड



धान की कटाई के बाद खेतों में बचे ठूंठ और डंटल (पराली) को जलाना भिण्ड जिले में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री पवन कुमार जैन ने मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग की 15 मई 2017 की अधिसूचना के अनुपालन में यह आदेश जारी किया है। उद्देश्य वायु प्रदूषण और आगजनी की घटनाओं पर रोक लगाना, जन-स्वास्थ्य व जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भूमि की उर्वरता बनाए रखना है। हार्वेस्टर संचालकों के लिए अनिवार्य निर्देशकलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक कंबाइन हार्वेस्टर संचालक फसल कटाई के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाकर खेत पर ही भूसा बनाएगा और फसल अवशेष का उचित निपटान करेगा। कटाई शुरू करने से पूर्व संचालक को कृषि विभाग के सहायक कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी भिंड कार्यालय में पंजीयन कराना होगा। संचालक अपनी एवं मशीन पर कार्यरत स्टाफ की जानकारी कृषि विभाग को देगा। सहायक कृषि यंत्री पंजीयन का रिकॉर्ड संधारित करेंगे और समय-समय पर राजस्व, कृषि एवं पुलिस विभाग को अवगत कराएंगे। यदि कोई किसान स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के बिना कटाई का दबाव बनाता है, तो हार्वेस्टर संचालक इसकी सूचना ग्राम पंचायत निगरानी अधिकारी, पंचायत सचिव, पुलिस थाना, नायब तहसीलदार, तहसीलदार या एसडीएम को तत्काल देगा। आगजनी रोकने हेतु मशीन में अग्नि सुरक्षा उपकरण के साथ रेत और पानी की व्यवस्था भी रखना अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर यह होगा मुआवजा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुसार पराली जलाने पर भूमि मालिक को पर्यावरण मुआवजा देना होगा। मुआवजा भूमि क्षेत्र के आधार पर निर्धारित है। जिसमें छोटे भूमि मालिक जिनकी भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ से कम है, को पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 2500/- रूपये प्रति घटना देना होंगे। भूमि मालिक जिनकी भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ से अधिक व 5 एकड़ से कम है को पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 5000/- प्रति घटना देना होंगे। भूमि मालिक जिनकी भूमि का क्षेत्र 5 एकड़ से अधिक है को पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 15000/- प्रति घटना देना होंगे। पर्यावरण मुआवजे के निर्धारण और अर्थदंड हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकृत होंगे। उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। ट्रांसफार्मर के पास रहेगा 10×10 फिट का खुला क्षेत्र कलेक्टर ने मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री को पर्याप्त दल गठित कर ट्रांसफार्मरों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि शॉर्ट सर्किट या चिंगारी से फसल को नुकसान न हो। खतरा होने पर किसान की सहमति से ट्रांसफार्मर के आसपास 10×10 फिट का क्षेत्र खुला रखा जाएगा। सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अपने क्षेत्र में पराली जलाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बिना कटिंग मशीन के काम करने वाले हार्वेस्टरों को तत्काल जप्त कर थाने में रखवाने का निर्देश भी दिया गया है।

स्वामित्व योजना के अधिकार अभिलेखों की रजिस्ट्री के लिए एमपी ई-सेवा ऐप से घर बैठे कर सकेंगे आवेदन



■ एक सत बुलेटिन, भिण्ड

स्वामित्व योजना के अंतर्गत निर्मित अधिकार अभिलेखों के पंजीयन (रजिस्ट्री) के लिए जिले के भूखंड एवं अधिकार अभिलेख धारक अब एमपी ई-सेवा ऐप के माध्यम से स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस सुविधा से हितग्राही निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम मोबाइल में एमपी ई-सेवा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप खोलने के बाद समग्र आईडी के माध्यम से ओटीपी प्राप्त कर लॉगिन करना होगा। इसके बाद स्वामित्व दस्तावेज आवेदन विकल्प का चयन करने पर संबंधित भूखंडों की सूची प्रदर्शित होगी। आवेदक को जिस भूखंड के लिए आवेदन करना है, उसका चयन कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। आवेदन प्रक्रिया के अगले चरण में आधार ई-केवाईसी के माध्यम से पहचान सत्यापन करना होगा। इसके पश्चात वीडियो रिकॉर्डिंग का विकल्प सक्रिय हो जाएगा। इस विकल्प के माध्यम से सभी संबंधित भूमिस्वामियों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी तथा उनकी सहमति 'हाँ' अथवा 'नहीं' बोलकर दर्ज की जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग पूर्ण होने के बाद आवेदक गवाह जोड़ने के विकल्प का चयन कर सकते हैं। यदि तत्काल गवाह जोड़ना चाहते हैं, तो 'हाँ' विकल्प चुनें।

सहकारी संस्थाओं से प्रमाणित बीज क्रय करने की अपील बीज खरीदते समय टैग बिल एवं बीज की वैधता जांच कर लें



■ एक सत बुलेटिन, भिण्ड

किसानों को आगामी रबी मौसम में गुणवत्तापूर्ण बीज की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जिलों में शासकीय एवं अन्य अधिकृत संस्थाओं के पास विभिन्न फसलों के बीज का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जिलों में बीज की उपलब्धता की निरंतर समीक्षा की जा रही है तथा किसानों की मांग एवं आवश्यकता के अनुसार बीज की उपलब्धता पर्याप्त है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम में 91452 क्विंटल, शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों में 12403 क्विंटल, बीज संघ में 652739 क्विंटल, राष्ट्रीय बीज निगम में 255718 क्विंटल, अन्य अधिकृत संस्थाओं में 190839 क्विंटल, इस प्रकार संस्थागत में 1203191 क्विंटल एवं निजी बीज संस्थाओं में 2548843 क्विंटल उपलब्ध है। इस प्रकार कुल 3751994 (सैतीस लाख इक्यावन हजार नौ सौ चौरान्वे) क्विवंटल चना, मसूर, सरसों, अलसी, मटर, गेहूं एवं जौ बीज उपलब्ध है। भिण्ड जिले में बीज संघ में 900 क्विंटल, राष्ट्रीय बीज निगम में 15517 क्विंटल सरसों का बीज उपलब्ध है। इस प्रकार कुल 16417 क्विंटल सरसों का बीज उपलब्ध है। किसान भाईयों से अपील है कि, वे अधिकृत विक्रय केन्द्रों एवं संबंधित सहकारी संस्थाओं से प्रमाणित बीज क्रय कर सकते हैं तथा बीज खरीदते समय टैग, बिल एवं बीज की वैधता जांच कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बीज विक्रय होने पर कृषकगण संबंधित जिले के कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना दे सकते हैं।जिले में रबी सीजन की बोवनी को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त बीज की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में जिले में 16,417 क्विंटल सरसों का प्रमाणित बीज उपलब्ध है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अधिकृत विक्रय केंद्रों एवं संबंधित सहकारी संस्थाओं से ही प्रमाणित बीज का क्रय करें। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को सलाह दी है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें।

रबी सीजन के लिए प्रदेश में 37.51 लाख क्विंटल से अधिक बीज उपलब्ध किसानों की मांग के अनुरूप पर्याप्त भंडारण

मुरैना! आगामी रबी सीजन में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में बीज का भंडारण किया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किसानों की मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न रबी फसलों के प्रमाणित एवं आधार बीज की उपलब्धता की निरंतर समीक्षा की जा रही है, ताकि किसानों को समय पर बीज मिल सके और बुवाई में किसी प्रकार की परेशानी न हो। विभाग के अनुसार, प्रदेश में शासकीय एवं अन्य अधिकृत संस्थाओं तथा निजी बीज संस्थाओं के पास कुल 37 लाख 51 हजार 994 क्विंटल बीज उपलब्ध है। इसमें गेहूं, चना, मसूर, सरसों, अलसी, मटर एवं जौ सहित रबी सीजन की प्रमुख फसलों के बीज शामिल हैं। विभाग द्वारा बीज के भंडारण एवं उपलब्धता की सतत निगरानी की जा रही है, जिससे किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बीज उपलब्ध कराया जा सके। मुरैना जिले में भी बीज का पर्याप्त भंडारण रबी वर्ष 2026-27 के लिए मुरैना जिले में भी विभिन्न फसलों के प्रमाणित एवं आधार बीज उपलब्ध कराए गए हैं। जिले में संस्थावार उपलब्धता के अनुसार गेहूं का 3,220 क्विंटल, चना का 950 क्विंटल, जौ का 2,675 क्विंटल तथा सरसों का 1,500 क्विंटल बीज उपलब्ध है।

भूखंड एवं अधिकार अभिलेख धारक स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे

स्वामित्व योजना के अधिकार अभिलेखों की रजिस्ट्री के लिए एमपी ई-सेवा ऐप से घर बैठे कर सकेंगे आवेदन

■ एक सत बुलेटिन, भिण्ड



स्वामित्व योजना के अंतर्गत निर्मित अधिकार अभिलेखों के पंजीयन (रजिस्ट्री) के लिए जिले के भूखंड एवं अधिकार अभिलेख धारक अब एमपी ई-सेवा ऐप के माध्यम से स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस सुविधा से हितग्राही निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम मोबाइल में एमपी ई-सेवा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप खोलने के बाद समग्र आईडी के माध्यम से ओटीपी प्राप्त कर लॉगिन करना होगा। इसके बाद स्वामित्व दस्तावेज आवेदन विकल्प का चयन करने पर संबंधित भूखंडों की सूची प्रदर्शित होगी। आवेदक को जिस भूखंड के लिए आवेदन करना है, उसका चयन कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। आवेदन प्रक्रिया के अगले चरण में आधार ई-केवाईसी के माध्यम से पहचान सत्यापन करना होगा। इसके पश्चात वीडियो रिकॉर्डिंग का विकल्प सक्रिय हो जाएगा। इस विकल्प के माध्यम से सभी संबंधित भूमिस्वामियों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी तथा उनकी सहमति 'हाँ' अथवा 'नहीं' बोलकर दर्ज की जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग पूर्ण होने के बाद आवेदक गवाह जोड़ने के विकल्प का चयन कर सकते हैं। यदि तत्काल गवाह जोड़ना चाहते हैं, तो 'हाँ' विकल्प चुनें। अन्यथा 'नहीं' विकल्प का चयन करने पर पटवारी द्वारा सत्यापन की कार्यवाही के दौरान संबंधित भूखंडों की सूची प्रदर्शित होगी। आवेदक को जिस भूखंड के लिए आवेदन करना है, उसका चयन कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। आवेदन प्रक्रिया के अगले चरण में आधार ई-केवाईसी के माध्यम से पहचान सत्यापन करना होगा। इसके पश्चात वीडियो रिकॉर्डिंग का विकल्प सक्रिय हो जाएगा। इस विकल्प के माध्यम से सभी संबंधित भूमिस्वामियों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी तथा उनकी सहमति 'हाँ' अथवा 'नहीं' बोलकर दर्ज की जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग पूर्ण होने के बाद आवेदक गवाह जोड़ने के विकल्प का चयन कर सकते हैं। यदि तत्काल गवाह जोड़ना चाहते हैं, तो 'हाँ' विकल्प चुनें। अन्यथा 'नहीं' विकल्प का चयन करने पर पटवारी द्वारा सत्यापन की कार्यवाही के दौरान गवाह जोड़े जा सकेंगे। इसके बाद 'सेव करें तथा आगे बढ़ें' विकल्प पर क्लिक कर अगले चरण में भूखंड की चतुरसीमा सहित आवश्यक विवरण एवं अन्य जानकारी दर्ज करनी होगी। सभी विवरण भरने के बाद आवेदन पत्र का अवलोकन कर 'सबमिट' विकल्प पर क्लिक करने से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। आवेदन के लिए आवश्यक सावधानियां आवेदन के लिए समग्र आईडी अथवा आधार से लिंक मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए, ताकि ओटीपी प्राप्त किया जा सके। सभी भूमिस्वामियों एवं गवाहों की समग्र ई-केवाईसी पूर्ण होना आवश्यक है। साथ ही, संबंधित भूखंड का स्वामित्व योजना के अंतर्गत चिन्हित होना भी अनिवार्य है। संबंधित हितग्राहियों से अपील है कि वे निर्धारित पात्रता एवं आवश्यक शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए एमपी ई-सेवा ऐप के माध्यम से स्वयं आवेदन कर इस सुविधा का लाभ उठाएं।

पशुपालक 1962 पर कॉल लगाएं और घर पहुंच पशु चिकित्सा सेवा का लाभ उठाएं

■ एक सत बुलेटिन, भिण्ड



जिले में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संचालित 08 चलित पशु चिकित्सा इकाइयों से पशुपालकों को बड़ी राहत मिल रही है। अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 के दौरान इन इकाइयों द्वारा कुल 6,899 केस अटेंड किए गए। प्रतिदिन प्रति वाहन औसतन 05 केस का निरीक्षण एवं उपचार किया जा रहा है।इन इकाइयों के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के पशुपालकों को बीमार पशु को चिकित्सालय तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1962 पर कॉल करते ही चलित पशु चिकित्सा इकाई पशुपालक के घर या खेत पर पहुंचकर पशु की जांच, उपचार एवं आवश्यक सलाह उपलब्ध कराती है। विभाग का उद्देश्य है कि पशुओं को समय पर चिकित्सा मिले और पशुपालकों की आय में सुधार हो। अधिकारियों ने पशुपालकों से अपील की है कि पशु बीमार होने पर तुरंत 1962 पर संपर्क करें और घर पहुंच पशु चिकित्सा सेवा का लाभ उठाएं।

दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत नकली दूध एवं मावा के विरुद्ध प्रशासन सख्त

एक सत बुलेटिन, भिण्ड। कलेक्टर श्री पवन कुमार जैन के निर्देशानुसार दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत नकली दूध एवं मावा ले जाने वाले वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एसडीएम मेहगांव श्री नवनीत शर्मा ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती रीना बंसल के साथ वाहनों की चेकिंग की। जांच के दौरान मावा ले जा रहे एक पिकअप वाहन को रोका गया, जिसमें 1250 किलोग्राम मावा पाया गया। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 3.12 लाख रुपये बताई गई है। उक्त मावा को जप्त कर लिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्रवाई की जावेगी। प्रशासन त्यौहारी सीजन में उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु जांच अभियान निरंतर जारी रखेगा। आमजन से अपील है कि नकली दूध, मावा एवं अन्य खाद्य सामग्री नजर में आने पर संबंधित अनुभाग के एसडीएम या खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तत्काल सूचना दें, सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।



विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसरों के साथ युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण प्रकरण तैयार कराने की सुविधा भी मिलेगी

मुरैना में 27 अक्टूबर को युवा संगम (रोजगार मेला) आयोजित होगा

■ एक सत बुलेटिन, मुरैना

जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार, अप्रेंटिसशिप एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार कार्यालय, मुरैना द्वारा 27 अक्टूबर 2026 को एक दिवसीय युवा संगम (रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला) आयोजित किया जाएगा। मेला शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई), जरेरुआ के पास, ए.बी. रोड, मुरैना में प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा अपनी रिक्तियों के अनुसार पात्र युवाओं का चयन किया जाएगा। साथ ही, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ऋण प्रकरण तैयार कराने तथा ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा। मेले का उद्देश्य युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। मेले में वर्धमान फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, बुधनी द्वारा मशीन ऑपरेटर के पदों पर आठवीं, दसवीं एवं बारहवीं उत्तीर्ण 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को चयन का अवसर दिया जाएगा। इन पदों के लिए प्रारंभिक वेतन 12,500 से 18,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। जॉबकेयर नाउ प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर द्वारा डिप्टी मैनेजर के पद पर बी.कॉम (स्पेशल) उत्तीर्ण युवाओं का चयन किया जाएगा। इस पद के लिए आयु सीमा 21 से 28 वर्ष तथा वार्षिक वेतन पैकेज 4 लाख रुपये निर्धारित है। न्यू मैक्स स्किल एवं मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब द्वारा मशीन ऑपरेटर के पदों के लिए दसवीं, बारहवीं, आईटीआई एवं बी.टेक योग्यताधारी 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को अवसर दिया जाएगा। इन पदों के लिए 14,000 से 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन निर्धारित है। इसी प्रकार, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, मुरैना द्वारा बीमा अभिकर्ता के पदों पर दसवीं, बारहवीं उत्तीर्ण एवं स्नातक युवाओं को अवसर प्रदान किया जाएगा। इन पदों पर 7,000 रुपये के साथ अतिरिक्त कमीशन का प्रावधान है। ब्राट बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा सेल्स एग्जीक्यूटिव के पदों पर दसवीं, बारहवीं एवं स्नातक योग्यताधारी 18 से 36 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का चयन किया जाएगा। इन पदों के लिए 16,500 रुपये प्रतिमाह वेतन निर्धारित है। जिला रोजगार अधिकारी ने इच्छुक युवाओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर समग्र आईडी, रोजगार पंजीयन, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर रोजगार मेले में भाग लें। मेले में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर जिले में हुए बलराम कृषि महोत्सव को वीसी से संबोधित कर किसानों से किया संवाद

किसानों की समृद्धि और कृषि विकास पर है विशेष फोकस: मुख्यमंत्री मोहन यादव

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण नरसिंहपुर में हुए बलराम कृषि महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) से संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बलराम कृषि महोत्सव आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि नरसिंहपुर जिला खेती-किसानी और उन्नत कृषि पद्धतियों के लिए विशेष पहचान रखता है। यहां की कृषि और किसानों की मेहनत के उदाहरण देशभर में देखने को मिलते हैं। बलराम कृषि महोत्सव किसानों के सम्मान, कृषि विकास और उनकी समृद्धि के संकल्प को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए कृषि के साथ-साथ सिंचाई, जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना आवश्यक है। सरकार नदी जोड़ो अभियान सहित विभिन्न क्षेत्रों में कृषि एवं इससे जुड़े व्यवसायों के विकास के प्रयास कर रही है। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे



हैं। उन्होंने बलराम कृषि महोत्सव को किसानों के बीच कृषि संबंधी जानकारी, आधुनिक तकनीकों और उन्नत खेती के तरीकों को साझा करने का महत्वपूर्ण मंच बताकर किसानों से नई कृषि पद्धतियों को अपनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने किसानों से परम्परागत खेती के स्थान पर अब अधिक आमदनी देने वाली उन्नत खेती कर खेतों-खलिहानों और अपने जीवन को समृद्ध बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नरसिंहपुर जिले से उनका विशेष स्नेह रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी के कल्याण एवं समृद्धि की कामना की तथा किसानों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दीं। बलराम कृषि महोत्सव को मप्र राज्य सहकारी बैंक (अपैक्स बैंक) के प्रशासक श्री महेंद्र सिंह यादव ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है और उसकी समृद्धि से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भगवान बलराम की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाने की पहल किसानों के सम्मान और कृषि विकास को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तेंदूखेड़ा विधायक श्री विश्वनाथ सिंह पटेल, गोटेगांव विधायक श्री महेंद्र सिंह नागेश, पूर्व राज्यमंत्री श्री जालम सिंह पटेल, श्री कसान सिंह यादव एवं श्री रामसनेही पाठक ने भी संबोधित किया। प्राकृतिक खेती एवं आधुनिक कृषि यंत्रों की लगी प्रदर्शनी नरसिंहपुर मंडी प्रांगण में आधुनिक कृषि यंत्रों, ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों एवं कृषि नवाचारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिले के प्रगतिशील किसानों ने अपने नवाचारों के अनुभव भी साझा किए। इनमें ग्राम चीलाचौनकलां, विकासखंड नरसिंहपुर के श्री इन्द्रपाल पटेल शामिल है, जो नरवाई प्रबंधन एवं सुपर सीडर से बोनी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार विकासखंड चीचली के ग्राम पुसारिया की श्रीमती शिवानी कौरव प्राकृतिक खेती एवं केंचुआ खाद इकाई के माध्यम से कृषि को प्रोत्साहित कर रही हैं। विकासखंड गोटेगांव के ग्राम रीछा के श्री लक्ष्मण पटेल कृषक एवं प्राकृतिक ढाई/ड्रिप-डाल उत्पादन से संबंधित गतिविधियों में अपने अनुभव साझा किए।

एमपी टूरिज्म को आउटस्टैंडिंग टूरिज्म स्टेट ऑफ इंडिया अवॉर्ड



■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

एमपी टूरिज्म बोर्ड को ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 69वें राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं एग्जिबिशन में 'अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस - आउटस्टैंडिंग टूरिज्म स्टेट ऑफ इंडिया' से सम्मानित किया गया है। कोलकाता में 25 से 27 अक्टूबर तक आयोजित सम्मेलन में अपर प्रबंध संचालक एमपी टूरिज्म बोर्ड डॉ. अभय बेड़ेकर ने यह सम्मान ग्रहण किया। यह सम्मान प्रदेश के पर्यटन विकास, गंतव्य प्रचार और समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। उल्लेखनीय है कि यह उपलब्धि TAAI के 75वें स्थापना वर्ष समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर हासिल हुई है। सचिव पर्यटन और प्रबंध संचालक एमपी टूरिज्म बोर्ड डॉ. इलैयाराजा टी ने कहा कि प्रदेश की समृद्ध विरासत और प्राकृतिक विविधता इसे देश के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में अग्रणी बनाती है। राष्ट्रीय स्तर पर मिला यह सम्मान पर्यटन क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और उद्योग जगत के सहयोगियों के साथ समन्वय को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। एमपी टूरिज्म, पर्यटकों को उत्कृष्ट अनुभव उपलब्ध कराने तथा पर्यटन की नई संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

फेमिना मिस इंडिया एमपी धनश्री चौहान बनीं शो स्टॉपर

`थ्रेड ऑफ एमपी' फैशन शो में रैंप पर बिखरे मध्यप्रदेश की कला और संस्कृति के रंग





■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

फैशन, डिजाइनिंग और ग्लैमर की दुनिया को मध्यप्रदेश की पारंपरिक कला एवं सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हुए 'थ्रेड ऑफ एमपी' भव्य फैशन शो का आयोजन नर्मदापुरम रोड स्थित सेलेस्टियल पार्क होटल में किया गया। शो में डिजाइनर सीमा विश्वकर्मा के आकर्षक कलेक्शन के साथ प्रदेश की पारंपरिक चंदेरी, महेश्वरी और बाग प्रिंट की कलात्मक छटा रैंप पर देखने को मिली। फेमिना मिस इंडिया मध्यप्रदेश धनश्री चौहान शो स्टॉपर के रूप में आकर्षण का केंद्र रहीं। उन्होंने डिजाइनर ड्रेसेस प्रस्तुत कर फैशन और पारंपरिक परिधानों के खूबसूरत संगम को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में एक्सीलेंसी टाइम एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिओम जटिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

पारंपरिक प्रिंट और आधुनिक डिजाइन का संगम

डिजाइनर सीमा विश्वकर्मा के कलेक्शन में चंदेरी की नजाकत, महेश्वरी वस्त्रों की विशिष्ट बुनावट और बाग प्रिंट की पारंपरिक छाप को आधुनिक परिधानों के साथ प्रस्तुत किया गया। रैंप पर मॉडलों ने आकर्षक परिधानों के माध्यम से डिजाइन, रंग संयोजन और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। शो स्टॉपर धनश्री चौहान की रैंप वॉक विशेष आकर्षण रही। उनके द्वारा प्रस्तुत डिजाइनर ड्रेसेस ने पारंपरिक भारतीय परिधानों को नए अंदाज में पेश किया। फैशन शो में विभिन्न राउंड के माध्यम से परिधानों की विविधता, डिजाइनरों की कल्पनाशीलता और मॉडलों के आत्मविश्वास को प्रदर्शित किया गया। पारंपरिक परिधानों पर केंद्रित राउंड में मध्यप्रदेश की चंदेरी, महेश्वरी और बाग प्रिंट की विरासत को प्रमुखता मिली, जबकि डिजाइनर कलेक्शन के प्रदर्शन में आधुनिक कट, रंगों और स्टाइलिंग के प्रयोग देखने को मिले। समकालीन फैशन के बीच तालमेल को रेखांकित किया।

नजीराबाद थाना पुलिस ने 72 घंटे में सुलझाई बाइक चोरी की दो वारदातें

3 आरोपी गिरफ्तार डेढ़ लाख रुपये कीमत की चोरी गई दोनों मोटरसाइकिलें बरामद एक आरोपी फरार

■ एक सत बुलेटिन, **बैरसिया।**

नजीराबाद क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय नजीराबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दो अलग-अलग बाइक चोरी के मामलों का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई दोनों मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं जिनकी कुल कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये बताई गई है। वहीं मामले में एक अन्य आरोपी अभी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार पहली घटना में कस्बा नजीराबाद निवासी अनीश खान की हीरो होंडा शाइन मोटरसाइकिल दनांक 29 सितंबर 2026 को राधारमण बैंक के सामने से चोरी हो गई थी। इस मामले में थाना नजीराबाद में अपराध क्रमांक 242/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। वहीं दूसरी घटना में ग्राम देहरी माधो जिला विदिशा निवासी मुजम्मिल कुरैशी की होंडा एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक एक्क04 डब्ल्यू6158 दिनांक 21 अक्टूबर 2026 को सुनगा जोड़ से चोरी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 266/26 दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों



से आरोपियों तक पहुंची पुलिस दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक देहात भोपाल पंकज कुमार पाण्डे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सोनकर तथा एसडीओपी बैरसिया सुश्री वैशाली सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी नजीराबाद निरीक्षक सहबाज खान के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और तकनीकी संसाधनों की मदद से संदिग्धों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। पूछताछ और कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चोरी गई दोनों मोटरसाइकिलें बरामद कर लीं।

अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में शहरी विकास, निवेश और आधुनिक अधोसंरचना को मिलेगी नई दिशा

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 28 अक्टूबर , बुधवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में प्रदेश में शहरी विकास, निवेश संवर्धन, आधुनिक नगरीय अधोसंरचना, डिजिटल गवर्नेंस, किफायती आवास और जल सुरक्षा से जुड़ी संभावनाओं पर मंथन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने बताया कि अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 प्रदेश के शहरों को आधुनिक, सुविधायुक्त और निवेश के लिए अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मंच होगा। कॉन्क्लेव 2.0 के माध्यम से नगरीय विकास से जुड़ी परियोजनाओं, नीतिगत पहलों और नवाचार आधारित समाधानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही शहरी अधोसंरचना के विकास में निवेशकों और विकास साझेदारों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में विभिन्न नगरीय विकास परियोजनाओं का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्मित आवासों के साथ पुनर्घनत्वीकरण, कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र, जलप्रदाय, सीवरेज और नगरीय अधोसंरचना विकास से संबंधित कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं से शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में कार्य होगा। नगरीय विकास परियोजनाओं का उद्देश्य शहरों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना और बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना है।

विभाग की टीम ने पौने चार लाख घरों और 27 लाख कंटेनर का किया लार्वा सर्वे

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

जिले में मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए नियमित रूप से सर्वेक्षण, लार्वा नियंत्रण एवं अन्य वेक्टर कंट्रोल गतिविधियां की जा रही हैं। जिले में वर्तमान स्थिति नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार जन-जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से बीमारियों की रोकथाम की जानकारी भी दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा इस वर्ष लगभग पौने चार लाख घरों और 27 लाख कंटेनर का सर्वे किया गया है। भोपाल में इस साल डेंगू के 156 पॉजिटिव केस मिले हैं। जिले के लगभग डेढ़ दर्जन इलाकों में पिछले 3 सालों में डेंगू केसेस के पैटर्न



को देखते हुए विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार फीवर सर्वे, लार्वा सर्वे, लार्वा विनिष्टीकरण, आवश्यक छिड़काव गतिविधियां कर रही हैं। जिले की पाँचों सेंटिनेल साइट्स निरंतर क्रियाशील रखी गई हैं। इन प्रमुख केंद्रों–अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र , गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, जयप्रकाश चिकित्सालय तथा सिविल अस्पताल बैरागढ़ में मरीजों के लिए एलाइजा टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि कूलर, पानी की टंकियों, गमलों, पुराने टायरों एवं अन्य पात्रों में जमा पानी को नियमित रूप से साफ करें, ताकि मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सके। साथ ही आसपास स्वच्छता बनाए रखने, मच्छरदानी एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का उपयोग करने तथा बुखार आने पर लापरवाही न बरतते हुए तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाई जाए।

अवैध खाद परिवहन और नकली उर्वरक के कारोबार पर मप्र पुलिस की प्रभावी कार्रवाई

भोपाल। किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने, खाद की कालाबाजारी एवं अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने और नकली उर्वरक के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा कृषि विभाग के साथ समन्वय कर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विगत दो दिनों में खंडवा एवं छतरपुर जिले में की गई दो महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में कुल 2,230 बोरी खाद जब्त की गई है।



इनमें खंडवा में अवैध रूप से परिवहन की जा रही 1,500 बोरी यूक्खाद सहित तीन ट्रक तथा छतरपुर में 730 बोरी नकली उर्वरक खाद और परिवहन में प्रयुक्त लोडर वाहन जब्त किया गया है। 25 अक्टूबर को खंडवा जिले के थाना खालवा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रिछड़ीखेड़ा में कृषि विभाग तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने महाराष्ट्र राज्य के पंजीयन नंबर वाले तीन ट्रकों की जांच की। तीनों ट्रकों में 500-500 बोरी के हिसाब से कुल 1,500 बोरी यूक्खाद भरी हुई थी। जांच के दौरान उपलब्ध ट्रांसपोर्ट परमिट से पता चला कि खाद महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से धारणी स्थित दादाजी कृषि सेवा केन्द्र के पते पर भेजी जा रही थी, लेकिन निर्धारित गंतव्य के बजाय इसे खंडवा जिले के ग्राम रिछड़ीखेड़ा में परिवहन करते हुए पाया गया। मामले में कृषि विभाग के अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर थाना खालवा में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

रेल परिचालन में सतर्कता, तत्परता एवं सूझबूझ से संभावित दुर्घटनाओं को रोकने में दिया महत्वपूर्ण योगदान

डीआरएम त्यागी ने संरक्षा के प्रति सतर्क एवं कर्तव्यनिष्ठ 7 रेलकर्मियों को किया सम्मानित

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल में रेल परिचालन की संरक्षा सुनिश्चित करने तथा संभावित दुर्घटनाओं को रोकने में सतर्कता, तत्परता एवं कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देने वाले रेलकर्मियों को मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज त्यागी ने सम्मानित किया। इन रेलकर्मियों ने अपने कार्य के दौरान संभावित खतरों एवं तकनीकी खामियों की समय रहते पहचान कर संबंधित अधिकारियों को सूचित किया, जिससे आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकी। श्री प्रफुल्ल प्रकाश पुरोहित, ट्रॉलीमैन, गुलाबगंजः दिनांक 29 सितंबर 2026 को श्री पुरोहित ने गुलाबगंज स्टेशन के निकट एक मालगाड़ी के वैगन में ब्रेक जाम होने की स्थिति को देखा और तत्काल स्टेशन प्रबंधक को इसकी सूचना दी। इसके बाद पबई स्टेशन पर गाड़ी को रोककर जांच की गई, जिसमें वैगन का ब्रेक जाम पाया गया। उनकी सतर्कता से समय रहते तकनीकी खराबी का पता लगाने और संभावित दुर्घटना को रोकने में मदद मिली। श्री रामचरण पटेल, कांटेवाला, अशोक नगर एवं श्री कमलेश मीना, गुड्स ट्रेन मैनेजरः दिनांक 3 सितंबर 2026 को अशोक नगर स्टेशन पर गाड़ी की शंटिंग के दौरान संबंधित रेलकर्मियों ने वैगन में हाट एक्सल से संबंधित स्थिति पर सतर्कता बरती और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने में योगदान दिया। उनकी सजगता से रेल परिचालन की संरक्षा बनाए रखने में सहायता मिली। श्री मुकेश कुमार, ट्रैक मेंटेनर, एवं श्री



अवधेश शर्मा, ट्रैक , मोहनाः दिनांक 6 सितंबर 2026 को घाटीगांव-पनिहार सेक्शन में किलोमीटर संख्या 1289 से 1291 के मध्य ट्रैक पेट्रोलिंग के दौरान दोनों कर्मचारियों ने रेल पटरी पर भारी वर्षा के कारण ट्रैक पर पानी से संबंधित संभावित खतरे को समय रहते पहचाना। उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचना देकर आवश्यक संरक्षा कार्रवाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री कैलाश, ट्रैक मेंटेनर, अशोक नगरः दिनांक 02 सितंबर 2026 को श्री कैलाश ने किलोमीटर संख्या 999/08-10 पर डाउन ट्रैक में प्रातः 05:30 बजे वेल्ड क्रैक देखा। उन्होंने तत्काल वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (पी.वे.) श्री मुंगावली को इसकी सूचना दी तथा क्रैक पर पट्टी लगाकर सी-क्लैंप बांधा। उनकी सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई से रेल पटरी की खराबी को समय रहते अधिकारियों के संज्ञान में लाने और संरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। श्री धनराज मीना, उप स्टेशन प्रबंधक, शाडोराः दिनांक 11 सितंबर 2026 को शाडोरा स्टेशन से मालगाड़ी के प्रस्थान के दौरान श्री धनराज मीना ने गाड़ी के साथ जा रहे वैगन में असामान्य स्थिति देखी। उन्होंने वैगन में दुर्घटनाग्रस्त होने के संकेत एवं एक व्हील जाम होने की स्थिति पर सतर्कता बरतते हुए गाड़ी को शाडोरा स्टेशन पर जांच के लिए रुकवाया। जांच में वैगन का ब्रेक ब्लॉक जाम पाया गया। इसके बाद ब्रेक को रिलीज एवं आइसोलेट कर गाड़ी का पुनः संचालन सुनिश्चित किया गया। उनकी सजगता एवं समय पर की गई कार्रवाई से संभावित दुर्घटना को रोकने तथा रेल परिचालन की संरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। श्री राजेश कुमार, राजगढ़ः दिनांक 11 सितंबर 2026 को राजगढ़ स्टेशन पर रेल इंजन एवं परिचालन से संबंधित जांच के दौरान सतर्कता बरतते हुए आवश्यक तकनीकी जांच और सुधारात्मक कार्रवाई में योगदान दिया। उनके प्रयासों से रेल परिचालन को सुरक्षित बनाए रखने में सहायता मिली।

स्वामी एक सत प्रयास जनकल्याण समिति के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **अमित शर्मा** द्वारा प्रकाशन स्थल बी-9 विवेक विहार कॉलोनी, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.) पिन-474001 से प्रकाशित एवं सर्वोदय ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, नया बाजार केनरा बैंक के पास ग्वालियर (म.प्र.)-474001 से मुद्रित। स्थानीय संपादक राजीव शुक्ल* पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।
RNI - MPHIN/2019/79098/ E-mail: EKSATBULLETIN@GMAIL.COM, WWW.EKSATBULLETIN.IN, मार्केटिंग एवं अन्य जानकारी हेतु हेड ऑफिस संपर्क करें- ए-1 माचना कॉलोनी, शा.राजीव गांधी हाई स्कूल शिवाजी नगर 6 नंबर बस स्टाप पास भोपाल। फोनः 0755-4515227, मोबाइलः 9691653088